mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-02 अंक-231 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़
21 अगस्त 2026 शुक्रवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का तिहाड़ में निधन

सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद काट रहे थे; 3 केस में से एक में बरी, 2 में दोषी थे

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, सज्जन कुमार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था।

वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के तीन में दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। उन्हें एक केस में बरी कर दिया गया था।

सज्जन कुमार- 1980 में पहली बार दिल्ली के सांसद बने

सज्जन कुमार का जन्म 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में हुआ था। वे मैट्रिक तक पढ़े थे। उनकी राम कौर से शादी हुई थी। उनके एक बेटा और दो बेटियां हैं। उन्होंने 1977 में दिल्ली नगर निगम पार्षद के तौर पर राजनीति शुरू की।

बाद में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने। 1980 में पहली बार बाहरी दिल्ली से सांसद चुने गए। 1991 और 2004 में भी इसी सीट से सांसद रहे। संसद में उन्होंने शहरी विकास और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जुड़ी समितियों में काम किया।1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों ने सज्जन कुमार के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया।

शाह बोले: कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम न गाना देशविरोधी

उन्होंने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और विभाजन की नींव डाली

नई दिल्ली,एजेंसी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला और देशविरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था, उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। उन्होंने कहा- कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फैसले से दो-राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ।

शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा- वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। यह हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। BJP स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी। उनके लिए यह राजनीतिक मुद्दा है। दरअसल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 पैरा में से सिर्फ शुरुआती दो पैरा गाएगी। यह फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद के बाद आया।

शाह ने कहा- कांग्रेस संसद के कानून को नहीं मान रही

अमित शाह ने कहा, 'कांग्रेस का सिर्फ दो पैरा वंदे मातरम गाने का फैसला तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति है। देश में अब तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी।''1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। आज कांग्रेस उसी पुराने फैसले को फिर लागू कर रही है। 'देश की जनता को कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। BJP इसका जनता के बीच और विधानसभा में भी जोरदार विरोध करेगी।'

देहरादून में भारत-नेपाल की अहम बैठक शुरू

ब्रिटिश शासनकाल के नक्शों से सुलझाएंगे सीमा विवाद

● 2 दिन में 4 दौर की होगी वार्ता

देहरादून,एजेंसी। उत्तराखंड के देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर 14वीं संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठक शुरू हो गई है। मसूरी रोड स्थित एक निजी होटल में दो दिन तक चलने वाली बैठक में चार दौर की वार्ता होगी।

बैठक में सीमा विवाद, सीमा निर्धारण, सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सर्वे ऑफ इंडिया के ब्रिटिश शासनकालीन नक्शों और पुराने अभिलेखों के आधार पर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफ्ले कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्रालय, आईटीबीपी, सेना और सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी भी शामिल हैं।

ब्रिटिशकालीन नक्शों का होगा अध्ययन

बैठक का सबसे अहम मुद्दा भारत-नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद का समाधान रहेगा। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के पुराने रिकॉर्ड और ब्रिटिश शासनकालीन नक्शों का अध्ययन किया जाएगा। दोनों देशों के अधिकारी इन दस्तावेजों का मौजूदा भौगोलिक स्थिति से मिलान कर विवादित सीमा क्षेत्रों पर एक राय बनाने की कोशिश करेंगे। सीमा पर जमीन और सीमा निर्धारण से जुड़े मामलों में पुराने अभिलेखों की भूमिका अहम मानी जा रही है। अधिकारी ब्रिटिशकालीन नक्शों के साथ उपलब्ध अन्य दस्तावेजों और वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेंगे।

लिंग निर्धारण अपराध में पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती

सुप्रीम कोर्ट बोला:अस्पताल पर छापा मारने का अधिकार भी नहीं, अब स्पेशल टीम करेगी कार्रवाई

नई दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अब पुलिस भ्रूण का लिंग पता लगाने वाले मामलों पर FIR नहीं कर सकती। PCPNDT कानून के तहत अब एक स्पेशल टीम इन मामलों पर कार्रवाई करेगी। अब पुलिस अल्ट्रासाउंड सेंटर या अस्पताल पर छापा नहीं मार सकती।

जांच भी नहीं कर सकती पुलिस

बेंच ने कहा कि प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, 1994 से जुड़े मामलों में मेडिकल जानकारी और संवेदनशीलता की जरूरत हो सकती है।

- कोर्ट ने कहा कि PCPNDT कानून के तहत होने वाले अपराधों के लिए पुलिस मुख्य जांच अधिकारी नहीं है।
- पुलिस सीधे तौर पर न तो FIR कर सकती है और न ही डॉक्टरों या अस्पतालों के खिलाफ एक्शन ले सकती है।
- पुलिस सिर्फ तभी कार्रवाई कर सकती है, जब उपयुक्त प्राधिकारी उनसे मदद मांगे।

'वैवाहिक विवाद में कराया जा सकता है बच्चे का पैटरनिटी टेस्ट', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली,एजेंसी। शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वैवाहिक विवाद में बच्चे का पैटरनिटी टेस्ट कराया जा सकता है। यह मामला तब सामने आया जब एक पति ने अपनी पत्नी के कथित अनैतिक चरित्र के आधार पर तलाक मांगा और दावा किया कि वह बच्चे का बायोलॉजिकल पिता नहीं है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने उस महिला की याचिका खारिज कर दी जिसने बच्चे के पैटरनिटी टेस्ट का विरोध किया था। महिला का तर्क था कि कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को DNA टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, और उसके पति की तलाक की याचिका का फैसला पैटरनिटी टेस्ट के बिना ही किया जाना चाहिए।

डॉक्टरों को एक यूनिक आईडी मिलेगी

नेशनल मेडिकल कमीशन का प्रस्ताव

नई दिल्ली,एजेंसी। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने हर रजिस्टर्ड डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UID) देने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद एक बार राज्य मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने पर डॉक्टर को देश के किसी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए अलग से नया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लेना होगा।

प्रस्ताव के तहत डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की स्थिति और डॉक्टर के खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी दर्ज रहेगी। यह रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसे मरीज और अस्पताल भी देख सकेंगे।

खरगे ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सार्वजनिक जवाबदेही की मांग की

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट के हवाले से कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में पीएम केयर्स फंड में 8,452 करोड़ रुपये की राशि थी, जबकि इस दौरान महज 87.85 लाख रुपये खर्च किए गए, जो फंड की समाप्ति शेष राशि का करीब 0.01 प्रतिशत है। खरगे ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा प्रधानमंत्री के नाम वाले इस फंड को सार्वजनिक निगरानी की सामान्य व्यवस्थाओं से बाहर क्यों रखा गया है। आपातकालीन फंड में हजारों करोड़ रुपये जमा रहने और एक साल में उसकी शेष राशि का महज 0.01 प्रतिशत खर्च होने का औचित्य क्या है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष हैं, जबकि रक्षा, गृह और वित्त मंत्री इसके न्यासी हैं। फंड को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत योगदान और कर कटौती योग्य दान भी प्राप्त होते हैं। इसके बावजूद इसे सूचना का अधिकार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच और संसद के स्तर पर जवाबदेही से बाहर क्यों रखा गया। खरगे ने प्रधानमंत्री से दो सवाल किए। पहला, प्रधानमंत्री के नाम वाले फंड को सार्वजनिक जांच-पड़ताल की सामान्य व्यवस्थाओं से बाहर रखने का कारण क्या है? दूसरा, जब 2024-25 में फंड की समाप्ति शेष राशि का महज 0.01 प्रतिशत खर्च हुआ, तो हजारों करोड़ जमा रखने वाले आपातकालीन फंड का औचित्य क्या है? खरगे ने कहा कि उन्हें पीएम केयर्स फंड और उससे जुड़ी सार्वजनिक जवाबदेही के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने फंड की राशि, उसके उपयोग और निगरानी की व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

उल्लेखनीय है कि पीएम केयर्स फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी 2024-25 के ऑडिटेड खातों के मुताबिक, वर्ष 2020 में महज 2.25 लाख रुपये से शुरू हुए इस फंड में 31 मार्च 2025 तक 8,452 करोड़ रुपये जमा हो चुके थे। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में फंड को देश के भीतर से 479.04 करोड़ रुपये और विदेशों से करीब 92 लाख रुपये का दान मिला।

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग बोला: आरएसएस पर बैन लगे

यहां आने वाले संघ के नेताओं को सम्मान न मिले; भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क जाएंगे

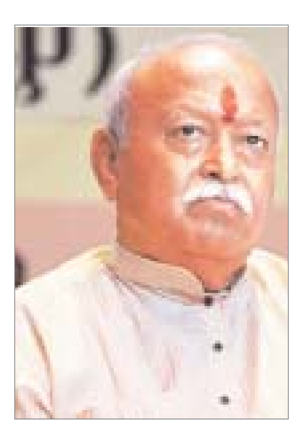

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से RSS नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने और उनके साथ उच्चस्तरीय बैठकें नहीं करने को कहा है।

आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS के सदस्य हैं और इसके सहयोगी संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं।

पाकिस्तानी मूल के महमूद का यह बयान RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ दिन पहले आया है। भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे।

भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD) के 'यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशंस' कार्यक्रम में शामिल होंगे।

भागवत सितंबर 2018 में अमेरिका गए थे और शिकागो में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस को संबोधित किया था। उपलब्ध रिपोर्टों में इस दौरे में उनकी किसी अमेरिकी राजनयिक से मुलाकात या औपचारिक राजनयिक सम्मान का जिक्र नहीं मिलता।

100 से ज्यादा संगठनों ने भागवत के कनाडा दौरे का समर्थन किया

कनाडा के 100 से ज्यादा संगठनों ने ऋरू प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित दौरे का समर्थन किया है। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और मंत्रियों को पत्र लिखकर भागवत कोरोकने की मांगों को खारिज करने की अपील की।संगठनों ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पुख्ता और स्वतंत्र सबूत होने चाहिए और कानून के मुताबिक पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब के सेवन से अब तक 6 की मौत, 21 अस्पताल में भर्ती

भावनगर,एजेंसी। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद भावनगर शहर और ग्रामीण इलाकों में कथित तौर पर जहरीली शराब के सेवन से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 21 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में उपचाराधीन हैं। बीती रात में पांच लोगों की मौत हो चुकी थी। आज सुबह एक और व्यक्ति ने दम तोड. दिया। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नही हुई है। इस घटना से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग ने जांच स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) को सौंप दी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने कथित तौर पर ब्रांडेड रॉयल स्टैग शराब की खाली बोतलें, ढक्कन और स्टिकर जुटाए और उनमें केमिकल मिश्रित जहरीला तरल भरकर नकली शराब के रूप में बेच दिया। एफएसएल और मेडिकल जांच के अनुसार, जहरीली शराब की चपेट में आए 10 मरीजों के रक्त और यूरिन सैंपल में करीब 38.59 प्रतिशत घातक मेथनॉल पाया गया, जबकि इथेनॉल की मात्रा केवल 0.94 प्रतिशत बताई गई है।

पुलिसकर्मी की पार्टी से सामने आया मामला :मामले की कड़ी पुलिस कर्मी की एक पार्टी के बाद सामने आई। 18 अगस्त को भावनगर जिले के पुलिस थानों को एलसीबी की ओर से सतर्क किया गया था। खरकड़ी गांव के रहने वाले विजयराजसिंह गोहिल का पुलिस भर्ती में चयन होने पर उन्होंने अपने दोस्तों उपेन्द्रसिंह गंभीरसिंह गोहिल, हरपालसिंह प्रदीपसिंह गोहिल और जयदीपसिंह राजेंद्रसिंह गोहिल को पार्टी दी थी। जयदीपसिंह को छोड़कर अन्य तीन दोस्तों ने कथित तौर पर रॉयल स्टैग शराब पी थी। इनमें से उपेन्द्रसिंह की 18 अगस्त को मौत हो गई।

अहमदाबाद से मंगाया गया केमिकल, उज्जैन से बुलाया गया 'डॉक्टर'

जांच के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क आर्थिक लाभ के लिए कथित रूप से एक सिंडिकेट के रूप में चलाया जा रहा था। वरतेज के नया प्लॉट इलाके की आंबलीवाली शेरी में रहने वाले कथित बुकी/बूटलेगर गौतम सोलंकी और रईस के बीच भावनगर में नकली शराब तैयार करने की डील हुई थी।

बताया गया है कि अहमदाबाद के सरखेज इलाके से सफेद तरल पदार्थ, खाली बोतलें, ढक्कन, स्टिकर और मेथनॉल मंगाया गया। केमिकल का मिश्रण तैयार करने के लिए उज्जैन से नरेंद्रसिंह उर्फ 'डॉक्टर' को बुलाया गया था।

पुलिस के अनुसार केमिकल मिश्रण तैयार करने वाले नरेंद्रसिंह ने खुद भी कथित तौर पर यही जहरीला तरल पी लिया था। उसकी तबीयत 17 अगस्त को बिगड़ी और 18 अगस्त को उसकी मौत हो गई।

दिल्ली दवा खरीद घोटाला: 650 करोड़ के मामले में अहम फाइलें नष्ट करने का आरोप,

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) में दवा और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुए 650 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण फाइलों को नष्ट किए जाने का आरोप सामने आया है। एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने कोर्ट में जानकारी दी है। कोर्ट में कहा, पहले गायब बताई जा रही घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों को जानबूझकर नष्ट किया गया। इन फाइलों में टेंडर, खरीद की दर, आपूर्ति, स्टाक और अधिकारियों की भूमिका से जुड़ी अहम जानकारी होने की संभावना थी। बताया कि पहले जिन 7 फाइलों के गायब होने की बात सामने आई थी, उनमें से प्रत्येक घोटाले की अलग कड़ी खोल सकती थी। फाइलें मिलतीं तो खरीद की प्रक्रिया से लेकर अस्पतालों तक आपूर्ति और भुगतान की स्थिति का मिलान किया जा सकता था।

सात फाइलों में छिपी थी घोटाले की कड़ी: करीब 16.67 लाख वस्तुओं की खरीद और करीब 75 करोड़ रुपये के खर्च का ब्योरा। इससे अस्पतालवार आपूर्ति, स्टाक और वास्तविक खपत का पता चलता। करीब 50 लाख सैशे की खरीद पर करीब 7.50 करोड़ रुपये खर्च का रिकार्ड। इससे पता चलता कि कितने सैशे किस अस्पताल को भेजे गए और कितना स्टाक बचा। 448 मशीनों की खरीद, कीमत, आपूर्ति, स्थापना और अस्पतालवार आवंटन का ब्योरा। इससे यह जांची जा सकती थी कि खरीदी गई सभी मशीनें वास्तव में अस्पतालों में पहुंचीं और स्थापित हुईं या नहीं। सात सी-आर्म मशीनों की करीब 7.70 करोड़ रुपये की खरीद का रिकार्ड। इससे खरीदी गई मशीनों के प्राप्तकर्ता अस्पताल और उनकी वर्तमान स्थिति का पता चलता।

खरीद, निरीक्षण, आपूर्ति और अस्पतालों में स्थापना से संबंधित विवरण। इससे यह पता चलता कि कितने उपकरण खरीदे गए और वास्तव में कितने अस्पतालों में लगाए गए। 100 करोड़ रुपये से अधिक की सर्जिकल सामग्री की खरीद का ब्योरा। इसमें ड्रेसिंग सामग्री, टांके, कैनुला और दस्ताने जैसी सामग्री शामिल थी। इससे खरीद की मात्रा, दर और अस्पतालवार आपूर्ति का मिलान किया जा सकता था। करीब 400 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद का रिकार्ड। इससे दवाओं की मात्रा, संबंधित कंपनियां, अस्पतालों को आपूर्ति और स्टाक रजिस्टर का मिलान कर यह पता लगाया जा सकता था कि खरीदी गई दवाएं वास्तव में कहां गईं।

448 एक्स-रे मशीनों पर 148 करोड़ खर्च

जांच में पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की खरीद पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि करीब 10 लाख रुपये की मशीन करीब 33 लाख रुपये प्रति मशीन की दर से खरीदी गई। 448 मशीनों पर करीब 148 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 45 करोड़ रुपये बताई गई है। बेडशीट करीब 150 रुपये के बजाय 450 रुपये में खरीदने का आरोप है। इस मद में करीब 75 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सी-आर्म करीब 25 लाख रुपये के बजाय 1.10 करोड़ रुपये प्रति मशीन की दर से खरीदे जाने का आरोप है। ओआरएस करीब 2.05 रुपये के बजाय 15 रुपये प्रति सैशे की दर से खरीदने का आरोप है। 18 मई 2026 को जांच टीम सीपीए से रिकार्ड लेने पहुंची थी। उस समय महत्वपूर्ण फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। अब एसीबी की ओर से कोर्ट में इन्हें नष्ट किए जाने की बात कहे जाने से मामले में साक्ष्य मिटाने का पहलू भी जुड़ गया है। वहीं, ई-टेंडर, भुगतान, लेखा और स्टाक से जुड़े डिजिटल रिकार्ड के जरिये इन फाइलों में दर्ज कई जानकारियां दोबारा जुटाई जा सकती हैं। इनसे टेंडर तैयार करने से लेकर खरीद की मंजूरी, आपूर्ति और भुगतान पाने वाली कंपनियों तक की पूरी कड़ी जोड़ने में मदद मिलेगी।

उत्तम नगर में अटल कैंटीन की शुरुआत, पांच रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार की अंत्योदय योजना के तहत राजधानी में अटल कैंटीन का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व प्रदेश में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जेजे कॉलोनी (ओल्ड पंखा रोड, मदर डेयरी के सामने) में नई अटल कैंटीन का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मजदूरों को मात्र 5 रुपये में स्वच्छ, संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। उद्घाटन के अवसर पर आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस पहल से अब कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चलाई जा रही है। यह व्यवस्था विशेषकर उन दिहाड़ी मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिनके पास समय या संसाधनों की कमी के कारण घर पर खाना बनाने की सुविधा नहीं होती।

दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन की शुरुआत की गई: शहरी विकास मंत्री ने जानकारी दी कि इससे दो दिन पूर्व भी दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन की शुरुआत की गई थी। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में राजधानी के विभिन्न इलाकों और झुग्गी-बस्तियों में इस कैंटीन श्रृंखला का तेजी से विस्तार करना है, ताकि हर जरूरतमंद तक सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंच सके। इसके साथ ही सरकार गरीब परिवारों को पक्के मकान देने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है।

सीजेपी करेगी स्कूलों का दौरा, राजस्थान के शिक्षा मंत्री को दी चुनौती

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था और शिक्षा विभाग द्वारा मीडिया के प्रवेश पर रोक लगाए जाने को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मीडिया पर रोक लगाकर सरकार स्कूलों की बदहाल स्थिति सार्वजनिक नहीं होने देना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह समन्वयक आशुतोष रांका ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का चुनौती देते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में सीजेपी की पूरी टीम के साथ राजस्थान के सरकारी स्कूलों का दौरा करेगी। रांका ने सोशल मीडिया पर शिक्षामंत्री को संबोधित करते हुए लिखा कि मदन दिलावर जी आपके लिए एक ऑफर है।

तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकते, तेलंगाना में मंत्री की बेटी ने ही दे डाली सीएम रेवंत रेड्डी को चुनौती

हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना कांग्रेस में चल रही बगावत अब खुलकर सामने आ गई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री की बेटी ने उन पर सार्वजनिक रूप से हमला किया है। रेड्डी सरकार में मंत्री कोंडा सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता ने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी है। पारकल में बोलते हुए बुधवार को सुष्मिता ने न केवल मौजूदा विधायक रेवूरी प्रकाश रेड्डी के लिए रेवंत रेड्डी के समर्थन को चुनौती दी, बल्कि उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए और उन्हें चुनावी चुनौती दी।

पारकल की विधायक तो मैं ही बनूंगी: सुष्मिता की बातें टिकट को लेकर होने वाले आम झगड़े से कहीं आगे की हैं। मौजूदा विधायक को मुख्यमंत्री का सार्वजनिक समर्थन मिलने पर उन्होंने कहा, ÷दो साल का इंतजार क्यों? उनसे अभी इस्तीफा देने को कहिए! उनसे कहिए कि इस्तीफा दें और चुनाव लड़ें।÷ इसके बाद उन्होंने ऐलान किया, चाहे आप आएं, आपके पिता आएं या आपके दादा आएं, पारकल की विधायक मैं ही बनूंगी।

अंहकारी हैं रेवंत रेड्डी: उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर अपना हमला और तेज करते हुए पूछा, ÷मेरा टिकट तय करने वाले रेवंत कौन होते हैं? उन्होंने रेवंत रेड्डी पर अहंकार का आरोप लगाया और कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस टीडी कांग्रेस बन गई है। साथ ही यह भी दावा किया कि पार्टी के मूल नेता पार्टी की दिशा से नाखुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के भाई से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जमीन सौदे का भी आरोप लगाया और चेतावनी दी कि वह रेवंत रेड्डी के परिवार से जुड़े अन्य कथित घोटालों का भी पर्दाफाश कर सकती हैं।

तेल-रासायनिक आपदा से निपटने की तैयारी परखेगा बंगाल, 21 अगस्त को पांच जिलों में मॉक ड्रिल

कोलकाता, एजेंसी। बंगाल के होटलों में लगातार हुए दो बड़े अग्निकांड की घटनाओं में 18 लोगों की मौत से राज्य सरकार चिंतित है। इन घटनाओं से सबक लेते हुए तेल एवं रासायनिक आपदा की स्थिति में राज्य की तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखने के लिए बंगाल सरकार का आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग 21 अगस्त को राज्यस्तरीय मॉक अभ्यास आयोजित करेगा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य के पांच जिलों में स्थित प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अभ्यास के लिए चुना गया है। इसमें संबंधित जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन तंत्र और औद्योगिक इकाइयों की आपात स्थिति से निपटने की क्षमता को परखा जाएगा। राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से बुधवार को एक बयान में बताया गया कि राज्यस्तरीय माक अभ्यास के लिए नदिया जिले में इंडियन आयल (आइओसीएल) के एलपीजी बाटलिंग प्लांट, पश्चिम बर्द्धमान में सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट, पूर्व बर्द्धमान में मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, मालदा में आईओसीएल के एलपीजी बाटलिंग प्लांट तथा दक्षिण 24 परगना में बीपीसीएल प्रतिष्ठान को शामिल किया गया है। अभ्यास के दौरान

तेल और रासायनिक पदार्थों से जुड़ी संभावित दुर्घटनाओं की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य, आपात प्रतिक्रिया, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रभावित क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई की तैयारियों का आकलन किया जाएगा।

आपदा की स्थिति में समन्वित कार्रवाई की होगी जांच: इस माक अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक आपदा की स्थिति में प्रशासन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संबंधित आपात सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। अभ्यास के माध्यम से संभावित कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि तेल या रासायनिक दुर्घटना की स्थिति में जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

हिमाचल में 25 साल बाद फिर शुरू होगी लॉटरी, किस्मत आजमाने से पहले जान लें नियम और शर्तें; खास मौके पर निकलेंगे बंपर ड्रॉ

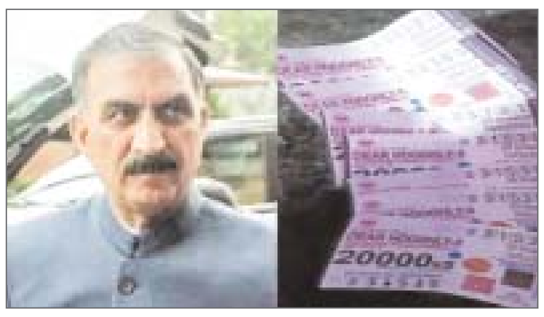

शिमला, एजेंसी। हिमाचल में करीब 25 साल से बंद लॉटरी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। वित्त विभाग के तहत निदेशालय कोषागार, लेखा एवं लॉटरी ने पेपर और ऑनलाइन लॉटरी की बिक्री के लिए सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने को ई-टेंडर जारी कर दिया है। सरकार ने लॉटरी संचालन को डिजिटल, पारदर्शी और कड़े नियमन के तहत चलाने की तैयारी की है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक प्रतिदिन अधिकतम 12 लॉटरी ड्रॉ आयोजित किए जा सकेंगे। इसके अलावा साल में तीन बंपर ड्रॉ होंगे। राष्ट्रीय महत्व के दिनों 26 जनवरी, 15 अगस्त और दो अक्टूबर को ड्रॉ आयोजित नहीं किया जाएगा। सभी ड्रॉ हिमाचल प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर ड्रॉ जजों की मौजूदगी में होंगे। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों और अधिकृत अधिकारियों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। डिजिटल ड्रॉ सिस्टम अपनाने का विकल्प भी रखा गया है।

सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व

सोल सेलिंग एजेंट को सरकार को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी। इसमें हर साल पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एजेंट को न्यूनतम छह करोड़ रुपये की वार्षिक गारंटीड राशि (एमजीए) देनी होगी। लॉटरी के कुल कारोबार पर कम से कम दो प्रतिशत रेवेन्यू शेयर की बोली लगानी होगी। सबसे अधिक रेवेन्यू शेयर की बोली लगाने वाले तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता को एच-1 घोषित किया जाएगा। सरकार ने एजेंट के लिए 30 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अनिवार्य की है। यह राशि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी अथवा एफडीआर के रूप में देनी होगी। प्रत्येक पेपर या ऑनलाइन ड्रॉ के लिए पांच हजार रुपये ड्रॉ खर्च भी एजेंट को देना होगा।

दो साल का होगा अनुबंध: चयनित एजेंट के साथ दो वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। प्रदर्शन संतोषजनक रहने पर सरकार अपने विवेक से इसे दो वर्ष और बढ़ा सकती है। लॉटरी संचालन के लिए एजेंट को स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) गठित करना होगा। बिक्री, वितरण, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड-कीपिंग और वित्तीय लेनदेन इसी व्यवस्था के तहत किए जाएंगे। इससे प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड और ऑडिट ट्रेल उपलब्ध रहेगा।

दो करोड़ ईएमडी, पांच लाख टेंडर फीस: टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों को दो करोड़ रुपये की ईएमडी जमा करनी होगी। टेंडर फीस पांच लाख रुपये निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले तकनीकी बोली के आधार पर कंपनियों के अनुभव, वित्तीय क्षमता और तकनीकी योग्यता की जांच होगी।

यूएनएससी में भारत की दो टूक: विकासशील देशों को मिले अधिक प्रतिनिधित्व, आतंकवाद पर राजनीति को लेकर क्या कहा

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के काम करने के तरीकों पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में भारत की राजदूत योजना पटेल ने देश का पक्ष रखा।उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में सार्थक योगदान देने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को दस्तावेजों तक पहुंच के मामले में एक जैसे अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

राजदूत योजना पटेल ने क्या कहा: योजना पटेल ने कहा कि जो देश सीधे तौर पर किसी मुद्दे से जुड़े हैं, उन्हें सुरक्षा परिषद के फैसले लेने की व्यवस्था में भी शामिल किया जाना चाहिए। खासकर शांति स्थापना से जुड़े सभी बड़े सवालों में उनकी भूमिका होनी चाहिए। इनमें मिशन का काम क्या होगा और उसके लिए कितने संसाधन दिए जाएंगे जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज संख्या- 507 में उचित बदलाव किया जाना चाहिए।

ईरान पर होगी सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई: ट्रंप ने दी धमकी, मदद करने वाले देशों को चेताया; क्या बढ़ेगा तनाव

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का सबसे बड़ा मौका दिया गया था। लेकिन उसने इसे गंवा दिया। ट्रंप ने कहा, इस्लामी गणराज्य ईरान को किसी समझौते के लिए मुझसे ज्यादा बड़ा मौका किसी ने नहीं दिया। दुख की बात है कि उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। इसलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा कर रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उसकी वायु सेना नष्ट हो गई है। उसकी सैन्य फैक्टरियां मलबे में बदल

गई हैं। ईरान की मुद्रा बेकार हो गई है और देश बेहद कमजोर स्थिति में है।

ईरान की मदद करने वाले देशों पर भी कार्रवाई: ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देगा, उसे भी बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसमें वित्तीय संस्थान, कारोबार, हवाई अड्डे और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, नकद लेनदेन, एक्सचेंज हाउस, जहाजों के पंजीकरण और ईरान की मदद करने वाली छिपी हुई (शेल) कंपनियों को तुरंत रोकने की बात कही।

सहयोगी देशों से अमेरिका के साथ आने की अपील: ट्रंप ने इसे ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक हमले का दिन बताया। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों से ईरान को अलग-थलग करने और उसके खतरे को खत्म करने में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है। उन्होंने दावा किया कि ये ऐतिहासिक कदम ईरान को और दुनियाभर में आतंक फैलाने की उसकी क्षमता को बुरी तरह कमजोर कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा।

अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया: अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के पिछले हफ्ते इसी तरह बयान दिया था। बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिशें बढ़ाएगा। इस रणनीति में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय %ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी% नाम से प्रतिबंध अभियान भी चला रहा है। इसका मकसद लक्षित कार्रवाई के जरिये ईरान के पैसे जुटाने के स्रोतों को बंद करना है।

ईरान के खिलाफ युद्ध कब शुरू हुआ: युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमलों के साथ हुई।

अमेरिका में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, भागवत के यूएस दौरे पर यूएससीआईआरएफ सख्त; बोला- संघ नेताओं को न मिले सम्मान

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाली सलाहकार संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वह आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान न दे और न ही उनके साथ किसी तरह की हाई-लेवल मीटिंग करे। यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिका दौरे से पहले आया है। वहीं, भारत पहले ही यूएससीआईआरएफ की रिपोर्टों को पक्षपातपूर्ण और वैचारिक पूर्वाग्रह पर आधारित बताते हुए खारिज कर चुका है। आरएसएस नेताओं से दूरी बनाने की अपील यूएससीआईआरएफ के चेयरमैन आसिफ महमूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। उन्होंने आरएसएस को एक %अंब्रेला ऑर्गनाइजेशन यानी ऐसा मुख्य संगठन

बताया, जिसके सहयोगी संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। महमूद की ये टिप्पणियां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ हफ्ते पहले सामने आई हैं। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग की ओर से आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन (एकता का उत्सव) में शामिल होने वाले हैं।

आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध की मांग: यूएससीआईआरएफ कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा कि आरएसएस नेताओं को, भले ही वे भारत सरकार से जुड़े हों, हाई-लेवल मीटिंग या राजनयिक सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, अमेरिकी सरकार को उन आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलीफ यानी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। यूएससीआईआरएफ ने आसिफ महमूद और जीन मिल्स की इन टिप्पणियों को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है।

महमूद ने आरएसएस को लेकर क्या कहा: महमूद ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। यह भारत का एक मुख्य संगठन है, जिसके सहयोगी समूहों ने ईसाइयों और मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। अब आरएसएस नेता मोहन भागवत अमेरिका का दौरा करने वाले हैं।

हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी उठाए सवाल: एडवोकेसी ग्रुप हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि मोहन भागवत के दौरे को मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आरएसएस नेटवर्क से जुड़े हिंसा के आरोपों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस एडवोकेसी ग्रुप ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि %एकता% का उत्सव धार्मिक श्रेष्ठता की राजनीति को छिपा नहीं सकता।

मार्च की रिपोर्ट में भी भारत पर निशाना: मार्च में यूएससीआईआरएफ की सालाना रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन को लेकर भारत की आलोचना की गई थी। रिपोर्ट में आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सहित कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं पर टारगेटेड प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया गया था। यूएससीआईआरएफ ने इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट खारिज की: भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। भारत का कहना है कि यह संस्था लगातार देश की गलत और चुनिंदा तस्वीर पेश करती है और उसकी रिपोर्ट संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक नैरेटिव पर आधारित होती हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 16 मार्च को एक बयान में कहा था कि यूएससीआईआरएफ को भारत की चुनिंदा आलोचना करने के बजाय अमेरिका में हिंदू मंदिरों में तोड़-फोड़ और हमलों की चिंताजनक घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता का संदेश: मझौली महाविद्यालय में कार्यशाला और प्रतियोगिताएं

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में 'भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अक्षय ऊर्जा' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई प्राचार्य डॉ. गीता भारती के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के संबंध में जानकारी दी गई कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि भारतीय चिंतन में प्रकृति और ऊर्जा को जीवन का अभिन्न आधार माना गया है सूर्य, वायु और अग्नि के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा सतत विकास की आधारशिला है सह-वक्ता राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि अक्षय ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है इसके लिए जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है प्राचार्य डॉ. गीता भारती ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकृति के साथ संतुलन और संधारण पर आधारित है उन्होंने विद्यार्थियों से प्रकृति संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग को व्यवहार में अपनाने का आह्वान किया कार्यशाला के अंतर्गत निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। निबंध में दीक्षा गुप्ता प्रथम, संतोषी साहू द्वितीय और आशीष कुमार यादव तृतीय रहे ।

रीवा जिला कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न: संगठन सुदृढ़ीकरण और जनआंदोलनों को लेकर बनी रणनीति

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय, रीवा में आयोजित की गई बैठक जिला संगठन प्रभारी एवं पूर्व विधायक रामलखन सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य तथा जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, कांग्रेस कमेटियों के भौतिक सत्यापन, अनुशासन बनाए रखने और जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई बैठक की शुरुआत जिला अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा द्वारा नवनियुक्त जिला संगठन प्रभारी रामलखन सिंह पटेल के स्वागत से हुई। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्राप्त एजेंडे का वाचन किया गया। बैठक में ट्रस्ट के गठन एवं संचालन के संबंध में सदस्यों से जानकारी ली गई सदस्यों ने बताया कि जिले में पार्टी से संबंधित कोई ट्रस्ट वर्तमान में संचालित नहीं है इस पर कहा गया कि यदि भविष्य में किसी ट्रस्ट के गठन की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसका प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जाए।

जिला कांग्रेस कार्यालय का निर्माण जारी: बैठक में जिला कांग्रेस कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की भी जानकारी दी गई बताया गया कि कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसे आगामी छह से आठ माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है पदाधिकारियों ने संगठनात्मक गतिविधियों के लिए कार्यालय को महत्वपूर्ण बताया। बैठक में ग्राम पंचायत एवं वार्ड कांग्रेस कमेटियों के भौतिक सत्यापन की प्रगति की समीक्षा की गई विभिन्न विधानसभा प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत की त्योंथर, सिरमौर और गुढ़ विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश सत्यापन कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई शेष क्षेत्रों में भी सत्यापन कार्य को 8 जुलाई तक पूरा करने का निर्णय लिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर की कमेटियों को सक्रिय और व्यवस्थित करना जरूरी है। इसके लिए सत्यापन प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया।

सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता पर चिंता: बैठक में पार्टी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर होने वाली अनुशासनहीन गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई ऐसे मामलों की निगरानी और समीक्षा के लिए तीन या पांच सदस्यीय अनुशासन समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। समिति सोशल मीडिया से जुड़े मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी।

हर माह होंगे कम से कम दो जनआंदोलन: बैठक में स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन तेज करने का भी निर्णय लिया गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों के साथ स्थानीय मुद्दों को जोड़ते हुए प्रत्येक माह कम से कम दो जनआंदोलन आयोजित करने की रणनीति बनाई गई प्रारंभिक चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालयों में जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन किए जाएंगे आंदोलनों की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा को सौंपी गई। वे ब्लॉक अध्यक्षों, विधानसभा प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद आंदोलन की तिथियां घोषित करेंगे।

संगठन मजबूत करने का

ब्यौहारी सिविल अस्पताल में अनशन खत्म: 25 दिन में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सोनोग्राफी और डायलिसिस सुविधा शुरू करने का आश्वासन

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। ब्यौहारी सिविल अस्पताल में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर स्वतंत्रता दिवस से चल रहा आमरण अनशन गुरुवार सुबह प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया प्रशासन ने अनशनकारी को भरोसा दिलाया कि अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सोनोग्राफी और डायलिसिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और 25 दिनों के भीतर व्यवस्थाएं लागू करने का प्रयास किया जाएगा अनशन का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था लंबे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ, सोनोग्राफी और डायलिसिस की सुविधा नहीं होने के कारण स्थानीय मरीजों को उपचार के लिए शहडोल सहित अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था। प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

जल्द जॉइन करेंगी स्त्री रोग विशेषज्ञ: प्रशासन के अनुसार ब्यौहारी सिविल अस्पताल के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. बबीता खरे का स्थानांतरण किया जा चुका है हालांकि उन्होंने अभी अस्पताल में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही उनके जॉइन करने की उम्मीद है उनके आने से महिला मरीजों को स्त्री रोग संबंधी उपचार के लिए दूसरे शहरों में जाने से राहत मिलने की संभावना है।

टोकन से नि:शुल्क होगी सोनोग्राफी: सोनोग्राफी सुविधा को लेकर प्रशासन ने बताया कि अस्पताल आने वाले मरीजों को डॉ. आर.एस. पांडे के यहां सोनोग्राफी के लिए टोकन जारी किए जाएंगे टोकन के आधार पर सिविल अस्पताल के मरीजों की सोनोग्राफी नि:शुल्क कराई जाएगी इसके लिए होने वाले भुगतान की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा की जाएगी इससे मरीजों को निजी स्तर पर सोनोग्राफी कराने के खर्च से राहत मिलेगी।

डायलिसिस सुविधा की प्रक्रिया शुरू: ब्यौहारी सिविल अस्पताल में डायलिसिस सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है इसके शुरू होने के बाद किडनी के मरीजों को नियमित डायलिसिस के लिए शहडोल या अन्य दूरस्थ शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी हालांकि प्रशासन ने अभी डायलिसिस सेवा शुरू होने की निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। अस्पताल में ड्रेसिंग, बैंडेज और पट्टी सहित अन्य जरूरी चिकित्सा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया गया है।

ई-विकास 2.0 प्रणाली लागू: अब किसान जरूरत के अनुसार बिना बंधन खरीद सकेंगे खाद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने ई-विकास 2.0 प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू कर दी है नई व्यवस्था के तहत 20 अगस्त से उर्वरक वितरण शुरू किया गया है किसान संगठनों, निजी विक्रेताओं और अन्य हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर पोर्टल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं नई व्यवस्था में किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी एक उर्वरक की खरीद कर सकेंगे अब किसी दूसरे उर्वरक के साथ खाद खरीदने की अनिवार्य बाध्यता नहीं होगी किसान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की फसलवार अनुशंसित मात्रा के अनुसार अथवा उससे अधिक मात्रा में उर्वरक पहली बार में ही प्राप्त कर सकेंगे अतिरिक्त उर्वरक की मांग करने पर पहले 50 शब्दों में कारण लिखने की बाध्यता थी जिसे अब समाप्त कर दिया गया है इसके स्थान पर पोर्टल में ड्रॉप-डाउन विकल्प उपलब्ध कराया गया है जिससे किसानों के लिए प्रक्रिया आसान होगी। नई प्रणाली में उर्वरक की गणना प्रति हेक्टेयर बैग के आधार पर की जाएगी ई-टोकन जारी होने के बाद किसान यदि उसे निरस्त करना चाहते हैं तो 24 घंटे बाद पोर्टल के माध्यम से टोकन निरस्त कर सकेंगे जल्द ही व्हाट्सऐप के माध्यम से टोकन, रिटेलर, उर्वरक की उपलब्धता और वैधता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधा भी शुरू की जाएगी फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में किसान ऑनलाइन अनुमति लेकर दोबारा उर्वरक की मांग कर सकेंगे ऐसे मामलों को एक्सेप्शनल हैंडलिंग के अंतर्गत रखा गया है संबंधित प्रकरणों को तहसीलदार अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा 48 घंटे के भीतर स्वीकृत किया जाएगा।

प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनिमेटरों से ही कराया जाए सोशल ऑडिट: शहडोल में संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। केंद्र और राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) का काम पूर्व से चयनित और प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनिमेटरों से ही कराने की मांग को लेकर ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ ने कलेक्टर शहडोल को ज्ञापन सौंपा संघ ने मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में बाहरी व्यक्तियों, निजी एजेंसियों और अप्रशिक्षित लोगों से सोशल ऑडिट कराने पर आपत्ति जताई है संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ग्राम सामाजिक एनिमेटरों का चयन शासन की निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया है चयन के बाद उन्हें सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित विधिवत प्रशिक्षण भी दिया गया है ये एनिमेटर मनरेगा सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के सोशल ऑडिट में पहले से काम करते आ रहे हैं संघ ने ज्ञापन में कहा कि ग्राम सामाजिक एनिमेटरों को ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी है ऐसे में उनके अनुभव का उपयोग सामाजिक अंकेक्षण के कार्य में किया जाना अधिक प्रभावी और उपयोगी हो सकता है संघ का दावा है कि प्रशिक्षित एनिमेटरों को हटाकर बाहरी एजेंसियों या नए लोगों को जिम्मेदारी देने से पहले से उपलब्ध अनुभवी मानव संसाधन का उपयोग नहीं हो पाएगा इससे न केवल प्रशिक्षित लोगों के अनुभव की अनदेखी होगी बल्कि नए लोगों को प्रशिक्षण देने में समय और सरकारी धन भी खर्च होगा।

निजी एजेंसियों को काम देने का विरोध: ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ ने विभिन्न योजनाओं के सोशल ऑडिट का काम निजी एजेंसियों, बाहरी व्यक्तियों अथवा अन्य संस्थाओं को दिए जाने का विरोध किया है संघ ने शासन से मांग की है कि सोशल ऑडिट के लिए पहले से चयनित और प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनिमेटरों को ही प्राथमिकता दी जाए ज्ञापन में कहा गया कि इन एनिमेटरों ने वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया है उनके अनुभव और प्रशिक्षण का लाभ शासन को लेना चाहिए संघ ने प्रशिक्षित मानव संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की मांग की है।

भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विविध कार्यक्रम: विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति किया जागरूक

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, सीधी में ऊर्जा संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अक्षय ऊर्जा के महत्व, इसके विभिन्न स्रोतों और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई कार्यक्रम का विषय परिचय डॉ. बृजेश सिंह चौहान ने कराया। इस दौरान 'प्राचीन ग्रंथों में अक्षय ऊर्जा से संबंधित उपबंध' विषय पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। सहायक प्राध्यापक रसायन विज्ञान डॉ. उमाकांत साहू ने अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान समय में अक्षय ऊर्जा पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि समय रहते ऊर्जा संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ाई गई तो भविष्य में ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अक्षय ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर: डॉ. सत्य प्रकाश शुक्ला ने कहा कि अक्षय ऊर्जा सभी के लिए महत्वपूर्ण पूंजी है इसका संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है उन्होंने विद्यार्थियों से ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को रोकने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय ऋषि-मुनियों द्वारा अक्षय ऊर्जा के उत्पादन एवं संरक्षण की अवधारणा पर आधारित लघु चलचित्र और चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े विचारों से परिचित कराया गया।

निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने लिया भाग: विद्यार्थियों की रचनात्मक सहभागिता बढ़ाने के लिए 'भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अक्षय ऊर्जा' विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई इसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. के.एस. नेताम ने कहा कि वर्तमान समय में ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है विद्यार्थियों को अक्षय ऊर्जा के महत्व से जोड़ना भविष्य में जिम्मेदार और पर्यावरण-संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने ऊर्जा संरक्षण तथा अक्षय ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग का संकल्प लिया।

पहली बारिश में ही बिजली विभाग की खुली पोल! कई सर्विस स्टेशन जलमग्न, दो में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप

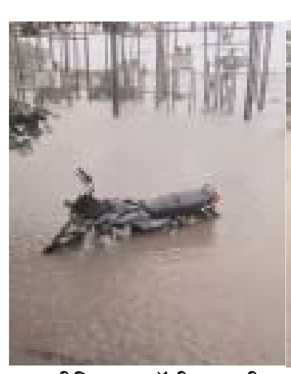

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में हुई पहली बारिश ने बिजली विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं बारिश के बाद रतहरा, करहिया, इटहा-छीजवार और अमहिया सहित कई क्षेत्रों के विद्युत सर्विस स्टेशनों में पानी भर गया जलभराव के कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दो सर्विस स्टेशनों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप होने की जानकारी सामने आई है बारिश के बाद सर्विस स्टेशनों में पानी भरने से विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है विद्युत व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण इन केंद्रों में जलभराव की स्थिति बनी रहने से उपकरणों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है इटहा-छीजवार क्षेत्र में भी बिजली लाइन प्रभावित होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून आने से पहले विद्युत सर्विस स्टेशनों में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इसके अलावा जलभराव वाले स्थानों पर जरूरी रखरखाव और सुरक्षा के उपाय किए जाने की आवश्यकता थी पहली बारिश में ही कई सर्विस स्टेशनों में पानी भरने से विभाग की मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों के मुताबिक यदि शुरुआती बारिश में ही बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो आने वाले दिनों में लगातार और तेज बारिश होने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है खासकर उन क्षेत्रों में जहां सर्विस स्टेशनों के आसपास पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है वहां विद्युत आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहेगा।

जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग: स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जलमग्न सर्विस स्टेशनों से तत्काल पानी निकासी कराने की मांग की है इसके साथ ही विद्युत उपकरणों की सुरक्षा जांच करने और प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने की मांग भी उठाई गई है।

सीधी शहर में सीवर लाइन सर्वेक्षण शुरू: डीपीआर तैयार होने के बाद होगा निर्माण, जलभराव और जल निकासी की समस्या कम होने की उम्मीद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शहर में बेहतर और व्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है विधायक रीती पाठक के प्रयासों से सीधी शहर में सीवर लाइन व्यवस्था विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है इसी क्रम में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीयूडीसी) की टीम ने सीवर लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया है सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाएगा आवश्यक स्वीकृतियां और अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सीवर लाइन निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा शहर में लंबे समय से व्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है बारिश के दौरान कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनने से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है प्रस्तावित सीवर लाइन परियोजना से घरेलू अपशिष्ट जल के व्यवस्थित निस्तारण के साथ जलभराव की समस्या को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है इसके साथ ही शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और भविष्य की आबादी के अनुरूप अधोसंरचना विकसित करने में भी यह परियोजना उपयोगी साबित हो सकती है।

कलेक्टर ने सर्वेक्षण टीम से ली जानकारी: एमपीयूडीसी की टीम द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण कार्य के संबंध में कलेक्टर विकास मिश्रा ने टीम से चर्चा की उन्होंने सीधी शहर की वर्तमान जल निकासी व्यवस्था, प्रमुख जलभराव वाले क्षेत्रों और भविष्य की आवश्यकताओं की जानकारी ली कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वेक्षण का कार्य व्यापक और तकनीकी रूप से सटीक तरीके से किया जाए ताकि इसके आधार पर तैयार होने वाली डीपीआर शहर की मौजूदा जरूरतों के साथ भविष्य के विस्तार को भी ध्यान में रखे कलेक्टर ने कहा कि सीवर लाइन की योजना तैयार करते समय शहर के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र का समुचित अध्ययन जरूरी है इसके लिए मौजूदा नालियों, जल निकासी मार्गों, जलभराव वाले स्थानों और संभावित सीवर नेटवर्क के मार्गों का तकनीकी अध्ययन करने के निर्देश दिए गए।

जलभराव वाले क्षेत्रों का होगा अध्ययन: सर्वेक्षण के दौरान एमपीयूडीसी की टीम शहर की भौगोलिक स्थिति और मौजूदा जल निकासी व्यवस्था का अध्ययन कर रही है इसके साथ ही भविष्य में विकसित किए जाने वाले सीवर नेटवर्क के तकनीकी पहलुओं का भी परीक्षण किया जा रहा है सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में सीवर लाइन की आवश्यकता है और नेटवर्क का स्वरूप किस प्रकार रखा जाना उपयुक्त होगा।

22 अगस्त को जिला अस्पताल सीधी में नि:शुल्क कैंसर परामर्श शिविर: स्तन, मुख और गले के कैंसर की होगी जांच

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में 22 अगस्त को जिला अस्पताल सीधी में नि:शुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों की जांच कर आवश्यक परामर्श देंगे उमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने बताया कि शिविर का उद्देश्य महिलाओं में स्तन कैंसर तथा आमजन में मुख और गले के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है साथ ही प्रारंभिक स्तर पर बीमारी की पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करना भी शिविर का प्रमुख उद्देश्य है शिविर में शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर की रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मालती भगत और कंसल्टेंट ऑन्कोसर्जन डॉ. प्रशांत जैन मरीजों की जांच एवं परामर्श करेंगे।

महिलाओं को स्व-परीक्षण की जानकारी: शिविर के दौरान महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी स्वयं स्तन परीक्षण की विधि भी समझाई जाएगी महिलाओं को मासिक धर्म समाप्त होने के 5 से 7 दिन बाद नियमित रूप से स्व-परीक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार क्लीनिकल स्तन जांच कराने की सलाह दी गई है।

‘विरोध’ से झुकीं व्यवस्थाएं

संपादकीय

देश भर में ‘विरोध’ एक असरदार मुहावरा और हथियार बन गया है। इसे सामुदायिक प्रयोग भी कह सकते हैं। लगता है कि कष्ट, अन्याय, शोषण इतनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं कि आखिरी विकल्प ‘विरोध’ ही बचा है। कई बार यह भी एहसास होता है कि ‘विरोध’ की जमात में अचानक महात्मा गांधी की चेतना जागृत हो उठी है और वह व्यवस्था की चूलें हिला देने पर आमादा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण, संयमी, इच्छा-शक्ति से भरपूर, व्यवस्था के प्रतिरोध और धमकियों को झेलते हुए ‘विरोध’ किए जा रहे हैं। वे कामयाब होकर अपना मकसद भी हासिल कर रहे हैं। यह जमात दिल्ली के जंतर-मंतर या रामलीला मैदान अथवा किन्हीं ‘कॉकरोचों’ से प्रेरित नहीं है, बल्कि दमन, भ्रष्टाचार और शोषण ने इसे संघर्ष करने को बाध्य किया है। दो उदाहरण अभूतपूर्व और अकल्पनीय लगते हैं। बारिश में भीगती स्कूली छात्राओं ने मुख्य सडक़ अवरुद्ध कर दी, क्योंकि वे स्कूल की नकारा, उपेक्षित व्यवस्थाओं से तंग आ चुकी थीं। न अध्यापक, न सुरक्षित क्लास रूम, न स्वच्छ शौचालय और न ही पोषक दोपहर का भोजन..!

इस विरोध-प्रदर्शन ने सरकार और प्रशासन को हिला दिया, संबद्ध अधिकारी एकदम दौड़े चले आए और छात्राओं को आश्वस्त किया। विरोध समाप्त कर दिया गया। दूसरा उदाहरण बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली महू (मप्र) के पास का है। झार जिले के निसरपुर में ‘माता शबरी आवासीय कन्या छात्रावास’ में 60 छात्राओं की व्यवस्था थी, लेकिन वहां करीब 150 छात्राओं को ‘भेड़-बकरियों’ की तरह ठूंस कर रहने को विवश किया गया था। बीते रविवार की देर रात में 9वीं-11वीं कक्षा की 40 छात्राएं खिड़कियों से बाहर कूदीं, नंगे पांव चलती रहीं और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गईं। रात के अंधेरे में ही एसडीओ (पुलिस) और तहसीलदार दौड़े चले आए और छात्राओं की शिकायतें सुनीं। छात्रावास की वार्डन और कार्यवाहक प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। कमोबेश व्यवस्था को विरोध के सामने झुकना पड़ा। दरअसल ये तमाम ‘विरोध’ दिल्ली, रांची, पटना, लखनऊ, कोलकाता के विभिन्न विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों से भिन्न हैं। इन्हें न तो नौकरी चाहिए, न ही अभी उम्र है और न पेपरलीक या परीक्षा रद्द किए जाने के कारण भविष्य दांव पर है। इनका विरोध बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर है। बहरहाल रांची में अनशन, आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन विरोध, संघर्ष अब भी जारी है। अब वे 1932 नौकरीपेशा चेहरे आंदोलनरत हैं, जिनकी नौकरी छिन रही है। सोरेन सरकार ने 2014 के बाद की तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। परीक्षा रद्द, तो चयन भी रद्द और नतीजतन नौकरी भी खत्म...! यह बड़ी अजीब स्थिति है। अब ये नौजवान अदालत में जाएंगे। बिहार के पटना में करीब 70,000 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। वैसे सरकार में कुल 1.10 लाख से अधिक पद खाली हैं। विरोध और युवाओं की धमकी के मद्देनजर सरकार ने मात्र चार घंटे में ही 32,388 शिक्षकों की भर्ती और परीक्षा का विज्ञापन अधिसूचित कर दिया। बिहार में साल-दर-साल परीक्षाएं नहीं होतीं। स्नातक की डिग्री भी 5 साल में मिल पाती है। यदि परीक्षा होती है, तो परिणाम लटके रहते हैं।

सत्ताधारी दल के संगठन की चुनौतियां

राजीव सचान

अध्यक्ष बनने के लगभग सात महीने बाद नितिन नवीन की टीम घोषित हो गई। इसकी चर्चा इसलिए भी अधिक हो रही है, क्योंकि इसमें विलंब हुआ। किसी के लिए समझना कठिन है कि भाजपा अध्यक्ष को अपनी नई टीम बनाने में इतनी देर क्यों हुई? इस देरी का कारण जो भी हो, यह टीम एक ऐसे समय गठित हुई है, जब मोदी सरकार विपक्ष के आक्रामक तेवरों का सामना कर रही है। राजनीतिक इरादों से लैस नजर आने वाली काकरोच जनता पार्टी की ओर से नीट पेपर लीक मामले में आंदोलन छेड़ने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर अड़ जाने के बाद जो माहौल बना, उसका विपक्ष ने जमकर लाभ उठाया। इसी के नतीजे में संसद का मानसून सत्र न के बराबर चल सका।

सरकार जिस तरह संसद में गतिरोध तोड़ने में नाकाम रही, उससे यह संदेश निकला कि विपक्ष उस पर भारी पड़ा। सरकार यह भांप नहीं सकी कि विपक्ष केवल गोल पोस्ट बदलने ही नहीं, बल्कि उसे लेकर भाग खड़े होने की रणनीति पर चल रहा है।

नितिन नवीन की टीम को तत्काल प्रभाव से सक्रिय होना होगा, क्योंकि अगले वर्ष कम से कम सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश भी है। नितिन नवीन की टीम के सामने पार्टी और साथ ही केंद्र सरकार एवं अपनी राज्य सरकारों के पक्ष में भी नैरेटिव बनाने की चुनौती है। स्वाभाविक रूप से यह चुनौती उन राज्यों में अधिक होगी, जहां उसकी अपनी सरकारें हैं और जहां चुनाव भी निकट हैं, क्योंकि इन सरकारों के कामकाज के लिए वह उसी तरह जवाबदेह होगी, जैसे मोदी सरकार के कामकाज के लिए। निःसंदेह सत्ताधारी दलों के संगठनों को अपनी सरकारों का सहयोग और संरक्षण मिलने से कुछ सुविधा होती है, लेकिन जहां सत्ता से बाहर खड़े विपक्षी दलों को केवल विरोधी दलों की सरकारों की आलोचना-निंदा करना होता है, वहीं सत्ताधारी दलों के संगठनों को इसका प्रतिकार करने के साथ अपनी सरकार की नाकामियों पर भी जवाब देना होता है। यदि कोई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी न उतर पा रही हो और उसकी रीति-नीति से जनता में असंतोष बढ़ रहा हो तो उसका संगठन कितना भी सशक्त और तेज-तर्रार नेताओं से लैस क्यों न हो, उसे अपने पक्ष में नैरेटिव खड़ा करने में कठिनाई होगी। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद युवा और खासकर जेन-जी चर्चा में हैं। वे भाजपा के साथ अन्य सभी दलों की प्राथमिकता में आ गए हैं। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवाओं और नौजवानों का उल्लेख कई बार किया। इसी के कुछ दिन बाद नितिन नवीन की टीम घोषित हुई, लेकिन उनकी टीम की घोषणा के कुछ ही घंटे पहले खबर आ चुकी थी कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली यूजीसी-नेट के तीन विषयों की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। यह इसलिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि अनुवाद में गलतियां पाई गईं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता के साथ पीएचडी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में उसी एनटीए की ओर से तब गड़बड़ियां हुईं, जब नीट पेपर लीक के कारण उसकी फजीहत हो चुकी थी और उसकी तपिश मोदी सरकार को भी झेलनी पड़ी। इसे लापरवाही की पराकाष्ठा कहेंगे कि जिन तीन विषयों की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, उनके प्रश्न पत्रों में टाइपिंग की भी गलतियां थीं और कई प्रश्न ऐसे थे, जो पहले पूछे जा चुके थे। साफ है कि एनटीए का नाकारापन अब भी कायम है। या तो उसके अधिकारी लापरवाह हैं या फिर नाकारा। आखिर एनटीए के ऐसे कामकाज के बाद नितिन नवीन की टीम युवाओं को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकती है? उनकी टीम की घोषणा के पहले आई यह खबर भी चर्चा में रही कि नए बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में एक माह के अंदर ही इतने गड्ढे हो गए कि उन्हें गिनना भी कठिन हो रहा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता

भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने के साथ ही विकसित भारत के लिए ज्ञान-लोक गढ़ने वाली भी है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर अध्ययन, अध्यापन और शोध की प्रक्रिया भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो गई है। कई विश्वविद्यालयों में इस विषय पर अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और उच्च शिक्षण संस्थानों में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं।

बद्री नारायण

यह पहल हमें अपने सोच, विचार और मानसिकता में विद्यमान औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। अपनी ज्ञान परंपरा की खोज न केवल औपनिवेशिक शासन में रहे देशों में हो रही है, बल्कि चीन, जापान जैसे कई देश भी अपने राष्ट्रीय स्व को ज्ञान से जोड़ते हुए अपनी जड़, जमीन और संस्कृति में उपजे ज्ञान, मेधा, दक्षता और तकनीकी को अपनी आधुनिकता में शामिल कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध, अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया भारत में विलंब से शुरू हुई है। इसे आजादी के बाद से ही आरंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन यह संतोषजनक है कि शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में यह प्रक्रिया अब लगातार आगे बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा मात्र कोई विषय न होकर एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिससे हम अपने सभी विषयों और ज्ञान की अनुषंगी इकाइयों को समझ सकते हैं। यह एक दार्शनिक और सैद्धांतिक आयाम रचने के साथ ही अनुभवजन्य और प्रयोगसिद्ध प्रमाणों से भरे ज्ञान की उपयोगिता भी रखता है। इसमें उदाहरण और अनुभव भी शामिल हैं, जो हमारे पाठ्यक्रमों में आ रहे हैं। इसे केवल एक विषय के रूप में देखने की ग्रंथि से हमें मुक्त होना होगा।

भारतीय शिक्षा और विमर्श जगत की दूसरी समस्या यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध और संकलन के क्षेत्र में अभी कम काम हुआ है, जिसके कारण हमारे पास अध्ययन सामग्री का अभाव है। इस कमी को समझते हुए विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान अपने-अपने तरीके से इस दिशा में कार्यरत हैं। समाज विज्ञान से जुड़े शिक्षा संस्थानों में भारतीय समाज के ज्ञान, मेधा, तकनीकी पर शोध, संकलन और अध्ययन सामग्री बनाने का कार्य अभी पर्याप्त गुणात्मकता के साथ प्रारंभ हुआ है। अनेक विद्वान और समाजशास्त्री इस दिशा में कार्यरत हैं। इन शोधों का परिणाम शीघ्र ही दिखेगा। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित पाठ्यपुस्तकें बनाने के अभियान को खासा महत्व दिया है। अन्य विश्वविद्यालयों को भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज्ञान सृजन की परियोजना पर काम करना होगा। शिक्षा मंत्रालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज्ञान सृजन की प्रक्रिया को सहयोग देने के लिए एक उपखंड भी बनाया गया है, जो ऐसी परियोजनाओं को आर्थिक और दक्षता निर्माण में सहयोग करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनः खोज और उसे शोध एवं शिक्षण से जोड़ने की इस परियोजना की एक बड़ी समस्या इसके अर्थ का गलत पाठ और अनेक वृत्तांतात्मक उलझावों एवं अफवाहपूर्ण अवधारणाओं से गुजरना है। इस संदर्भ में पहली चुनौती इसके अर्थ एवं तत्व मीमांसा की है। भारतीय ज्ञान परंपरा वस्तुतः भारतीय समाज और उसके मिट्टी-पानी और सांस्कृतिक पर्यावरण में उपजा ज्ञान है। यह किसी एक जाति, पंथ और संस्कृति में सृजित एवं विकसित हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि यह उन सभी घटकों के सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव का ज्ञान समुच्चय है, जिनसे भारतीय समाज बनता है।

यह बहुलतावादी सामाजिक संस्कृति से उभरा ज्ञान है। यह भारतीय जमीन और पर्यावरण में पले-बढ़े हर संस्कृति के अनुभवों से उपजा ज्ञान है। अतः इसे किसी एक जाति, पंथ और संस्कृति में सीमित करना इसके तात्विक अर्थ का गलत पाठ करना है। हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी कोटियों से परे यह हर समुदाय, समाज एवं संस्कृति के लौकिक एवं दार्शनिक ज्ञान पर शोध-अध्ययन की हमें छूट देता है। एक तरफ वाल्मीकि, भरतमुनि, वेदव्यास, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, कौटिल्य का ज्ञान लोक भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है, दूसरी तरफ बुद्ध, नागार्जुन, भर्तृहरि, कबीर, नानक, रविदास के आख्यान इस ज्ञान विमर्श को रचते हैं। साथ ही अमीर खुसरो, दारा शिकोह तथा अन्य सूफियों का ज्ञान एवं योगियों का विमर्श भी इसमें शामिल है। तात्पर्य यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सीमांत पर बसे समुदायों, दलित, वंचित का ज्ञान अनुभव शामिल है, साथ ही अनेक धार्मिक-सांस्कृतिक समूहों के अनुभव भी इसमें शामिल हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का परिप्रेक्ष्य समाज की हर सामाजिक इकाई को एक सांस्कृतिक इकाई मानता है, जो अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों के बीच सांस्कृतिक, सभ्यतिक और आध्यात्मिक ज्ञान सृजित करता है। भारत में हर सामाजिक इकाई का एक लोक-जीवन होता है, जिसके अपने गीत, संगीत, सबद, भजन, कीर्तन, कव्वाली, मुहावरे, मसले होते हैं, जिनमें उन सामाजिक समूहों का ज्ञान, विवेक, तकनीकी, दक्षता और नीतियां भरी होती हैं। आवश्यकता है भारतीय लोक ज्ञान के इन सभी रूपों का व्यापक संकलन एवं शोध कर उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध रूपों को समझने एवं समझाने के लिए उपयोग किया जाए। इसमें स्त्री-पुरुष केंद्रित ज्ञान के साथ ही भारतीय समाज के हर चर-अचर के ज्ञानानुभव संग्रहित हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के इन रूपों में दर्शन, राजनीतिशास्त्र, आर्थिकी, धार्मिक, तकनीकी, चिकित्सकीय, लोक-व्यवहार के भारतीय संस्करण का विशाल भंडार है। इन्हें संकलित कर उनकी व्याख्या और पुनः पाठ करने की आवश्यकता है। हमें इनका आर्काइव विकसित कर उन पर शोध करना होगा और उन शोधों को पाठ्यक्रम में लाना होगा। साथ ही, इन पर उच्च कोटि की पाठ्यपुस्तकें भी विकसित करनी होंगी।भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित भारतीयता की व्यापकता एवं बहुलता के ज्ञान, नीतिगत, सांस्कृतिक एवं सभ्यतिक पक्षों पर शोध और अध्ययन करना होगा। इससे हमें अपने भारत को पुनःअविष्कृत करने में मदद मिलेगी। ज्ञान की यह पुनःखोज हमें स्वयं को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने के साथ ही विकसित भारत के लिए ज्ञान-लोक गढ़ने की भी निमित्त बनेगी।

फरक्का समझौते से न हो देश को क्षति

संजय कुमार झा

फरक्का जल संधि के पिछले तीन दशकों के अनुभव और आंकड़े ठोस प्रमाण हैं कि बिहार को इससे बाढ़ और सुखाड़ की दोहरी मार झेलनी पड़ी है। सितंबर 1996 में तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल (जो बाद में प्रधानमंत्री बने) द्वारा प्रतिपादित ‘गुजराल डाक्ट्रिन’ का मूल मंत्र था कि भारत को बड़ा दिल दिखाते हुए पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में ‘एकतरफा रियायत’ देनी चाहिए। विडंबना यह रही कि इस नीति के तहत दिसंबर 1996 में बांग्लादेश को जल-अधिकार सौंपते वक्त जब बिहार के हितों की बलि चढ़ाई जा रही थी, तब मुख्यमंत्री लालू यादव मौन साधे रहे, जो संयुक्त मोर्चा के एक प्रभावी नेता थे। केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी भी मूल रूप से बिहार के ही थे। यदि उसी समय संधि का विरोध हुआ होता, तो बिहार को बीते तीन दशकों में हुआ भारी नुकसान नहीं झेलना पड़ता। अब जबकि फरक्का जल संधि की 30 वर्षों की समयसीमा दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रही है, तब यह प्रश्न केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि व्यापक जनहित और जल-सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रहित से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। गंगा बिहार के लिए केवल एक पवित्र नदी ही नहीं, अपितु करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है। पेयजल, सिंचाई और उद्योग-धंधों के लिए पानी की उपलब्धता के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन तक गंगा के प्रवाह से जुड़ा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से कहते रहे हैं कि फरक्का बराज के कारण गंगा की अविरलता बाधित हुई। नदी में गाद की भरमार बढ़ी है। जल संसाधन मंत्री रहते हुए मैंने भी फरक्का बराज की संरचना और जल संधि के प्रविधानों पर पुनर्विचार का केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। संधि के प्रविधानों के अनुसार फरक्का बराज पर शुष्क मौसम (लीन पीरियड) में 1500 क्यूमेक जलस्राव सुनिश्चित किया जाना है, जबकि इसे पूरा करने के लिए बिहार को बक्सर में औसतन मात्र 400 क्यूमेक जलस्राव ही उपलब्ध हो पाता है। यानी निर्धारित जलस्राव का 73 प्रतिशत बोझ बिहार को वहन करना पड़ता है, जबकि गंगा का 75 प्रतिशत जलग्रहण क्षेत्र बिहार के अपस्ट्रीम राज्यों में है। इससे बिहार के उस नैसर्गिक अधिकार का हनन होता है, जो उसे गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल उपयोग पर मिलना चाहिए। फरक्का बराज के निर्माण का उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह और हुगली नदी में जल-प्रवाह बनाए रखना था। 1975 में बराज चालू होने के बाद गंगा की अविरलता बाधित हुई और अपस्ट्रीम में गाद की समस्या शुरू हो गई। आज बिहार में गंगा की लगभग पूरी 445 किमी लंबाई में अतिरिक्त गाद जमा है, जिससे नदी उथली होकर अपना मार्ग बदल रही है। मानसूनी वर्षा का जो पानी पहले गंगा की तलहटी में समा जाता था, अब आसपास के गांवों में बाढ़ लाता है। राज्य सरकार वर्षों से इस विषय पर केंद्र का ध्यान आकृष्ट कराती रही है, लेकिन राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति जैसी ठोस पहल अभी अमल में नहीं आ सकी है। इससे बिहार को जहां मानसून में बाढ़ की तबाही झेलनी पड़ती है, वहीं शुष्क मौसम में राज्य पानी की भारी किल्लत से भी जूझता है। हर साल सुखाड़ से प्रभावित होने वाले दक्षिण बिहार के जिलों में ही नहीं, बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित मिथिला के दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों में भी भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, सिंचाई प्रभावित हो रही है और पेयजल संकट गहरा रहा है। राज्य के जलाशयों की जल-संचयन क्षमता के विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में औसतन मात्र 35 प्रतिशत जल-संचयन हो सका है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। गंगा का प्रवाह बाधित होने और गाद भरने से बिहार के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा है। इससे राष्ट्रीय जलीय जीव ‘गांगेय डाल्फिन’ और स्थानीय मछलियों की कई प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। गंगा बेसिन के कई जिलों में आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे जहरीले रसायनों का असर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। गंगा नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो देश के लगभग 26 प्रतिशत भू-भाग को कवर करता है और देश की करीब 43 प्रतिशत से अधिक आबादी की पानी, कृषि और आजीविका की जरूरतों को पूरा करता है।1996 में अविभाजित बिहार की आबादी करीब 9.3 करोड़ थी, जिसमें वर्तमान बिहार की आबादी करीब 7.3 करोड़ थी। 2026 में यह आंकड़ा 13 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तीन दशकों में आबादी में 5.5 से छह करोड़ की वृद्धि के साथ पानी की मांग भी तेजी से बढ़ी है। बिहार सरकार ने वर्ष 2050 तक की भावी जल आवश्यकताओं का वैज्ञानिक आकलन कर केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के समक्ष कुल 2,000 क्यूसेक अतिरिक्त जल की मांग रखी थी, लेकिन समिति के अंतिम प्रतिवेदन में बिहार की पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए मात्र 900 क्यूसेक जल का ही प्रविधान किया गया। आधी से भी कम मांग स्वीकार किए जाने से आने वाले दशकों में बिहार की सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

कश्मीर पर अमेरिका का बदलता रुख

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने पहले जम्मू-कश्मीर दौरे में यहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद कश्मीर को भारत का अभिन्न और अहम भू-भाग बताया। सुरक्षा के लिहाज से सराहना की। अमेरिकी राजदूत का यह बयान अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर चौंकाने वाला होने के साथ अमेरिका-भारत के संबंधों में बदलाव का उल्लेखनीय संकेत है। लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की स्थिति भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विवाद के रूप में देखी जाती रही है।

प्रमोद भार्गव

जिसे अक्सर ‘भारतीय प्रशासन वाले कश्मीर’ जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। ऐसे में कश्मीर की धरती पर एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक का यह दो टूक बयान इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर कश्मीर को लेकर भारत की अखंडता एवं संप्रभुता की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान से पाकिस्तान को तो झटका लगा ही है, चीन भी सकते में है। अमेरिका ने वर्ष 2018 से ही जम्मू-कश्मीर के तात्कालिक पूर्वी लद्दाख और लेह को छोड़कर अपने नागरिकों को यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी हुई है। इस यात्रा चेतावनी को चौथी श्रेणी में रखा हुआ है। गोर ने फिलहाल इस यात्रा चेतावनी को कम करने का कोई संकेत नहीं दिया है लेकिन उम्मीद है कि इस बिंदु पर अमेरिका यात्रा में छूट दे सकता है। हालांकि उस समय अनुच्छेद-370 बहाल थी और घाटी में आतंकी संकट की छाया छाई रहती थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद-370 और 35-ए को भारत सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते विलोपित कर दिया, उसी के बाद से कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालातों में निरंतर सुधार हो रहे हैं और पत्थरबाजी व अन्य आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी विदेश

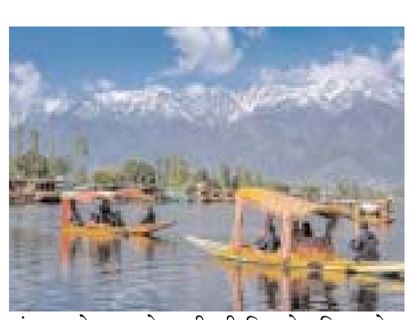

मंत्रालय ने उक्त चेतावनी की फिर से पुष्टि करते हुए नई एडवाइजरी जारी कर दी थी। जो अभी भी लागू है। चूंकि गोर दक्षिण एशिया व मध्य एशियाई मामलों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि हैं इसलिए उनकी कश्मीर यात्रा और दो टूक बयान की अपनी अहमियत है। खासतौर पर तब जब पाकिस्तान के संबंध भी अमेरिका के साथ फिलहाल मधुर बने हुए हैं और अमेरिका ईरान से लड़े जा रहे युद्ध में पाकिस्तान को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस बयान से उमर अब्दुल्ला को भी बड़ा झटका लगा है क्योंकि वे कुछ दिनों से अनुच्छेद-370 की पुर्नबहाली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जून 2026 में ‘द हिंदू हडल‘ (अंग्रेजी समाचार पत्र) सत्र के दौरान कहा था कि 2019 में 370 को हटाना भारत सरकार की सबसे बड़ी नीतिगत भूल थी। उन्होंने जम्मू-कशमीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और विशेष संवैधानिक अधिकारों की बहाली की भी मांग की थी। पाकिस्तान धर्म की घुट्टी पिलाकर 35 साल से भारत पर आतंकी हमले करता रहा है। जबकि उसे सबसे मुकम्मल जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया था लेकिन वह बाज नहीं आ रहा है। गैर-कश्मीरियों और हिंदुओं की हत्या के लिए उसकी क्रूरता समाप्त नहीं हो रही है। जाहिर है, पाकिस्तान भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बदले को भूल गया है। उसे एक बार फिर करारा जबाव देना होगा। दरअसल, इस समय पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में चल रहे आजादी के आंदोलन से भी जूझ रहा है। वहां भी उसने निर्ममता बरतते हुए सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों को भूनने का काम किया है। पाक की ये हरकतें इसलिए भी बरकरार हैं क्योंकि ईरान हमले में उलझा अमेरिका उसकी पीठ थपथपाने में लगा है। ऐसे में भारत को अनेक कूटनीतिक कदम उठाकर पाकिस्तान को विवश करना पड़ रहा है। अब जाकर उसे कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका का दो टूक जवाब मिला है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद भी हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है तो इसका एक बड़ा कारण मजहबी कट्टरता पर चोट नहीं कर पाना है। साफ है कि यह समस्या अब राजनैतिक व संवैधानिक नहीं रह गई है बल्कि धार्मिक चरमपंथ के रूप में सामने आ रही है। इस हिंसक उन्माद का सोच पाकिस्तान से निर्यात आतंकवाद तो है ही, घाटी में कुकुरमुत्तों की तरह मस्जिदों और मदरसों में फैला, वह शिक्षा का तंत्र भी है, जो आतंक की फसल बोने और उगाने का काम करता है। यही वजह है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनमें न तो अल्पसंख्यकों का जनसंख्यात्मक घनत्व बढ़ रहा है और न ही उन्हें नागरिक समानता के अधिकार मिल रहे हैं। कश्मीर में भी जिहादी चाहते हैं कि गैर-मुस्लिम या तो इस्लाम स्वीकार करें या फिर घाटी छोड़ जाएं। इस दोषपूर्ण मंशा को संविधान निर्माण के समय ही डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समझ लिया था। शेख अब्दुल्ला ने जब जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग की तो अंबेडकर ने सख्त लहजे में कहा था कि ‘आप चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों की आर्थिक सुरक्षा करे, कश्मीरियों को संपूर्ण भारत में समानता का अधिकार मिले लेकिन भारत और अन्य भारतीयों को आप कश्मीर में कोई अधिकार देना नहीं चाहते? मैं देश का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ कोई अन्याय या विश्वासघात किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूं।‘ नेहरू के अनावश्यक दखल से कश्मीर को विशेष दर्जा मिल गया। इस भिन्नता का संकट देश बंटवारे से लेकर अबतक भुगत रहा है। यही वजह है कि इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू, बौद्ध, सिख और दलित शरणार्थी के रूप में जम्मू-कश्मीर में ही ठहर गए थे, उन्हें मौलिक अधिकार अनुच्छेद-370 हटने के बाद मिल पाए हैं। इनकी संख्या करीब 70-80 लाख है, ये 56 शरणार्थी शिविरों में सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से महरूम रहते हुए बद से बदतर जिंदगी का अभिशाप अनुच्छेद-370 हटने से पहले तक भोगते रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जितने भी आतंकी हमले कश्मीर में हुए हैं, उनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली थी। यह लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है। यह लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों की आतंकी हरकतों को अंजाम देता है। भारतीय सेना ने कोटली अब्बास में जिस आतंकी शिविरों को तबाह किया किया था, इसमें 1500 आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया था। मुरीदके में जिस मरकज तैयबा को ध्वस्त किया गया था, यहां लश्कर का मुख्यालय माना जाता है। यहीं से मुंबई हमले का प्रमुख आतंकी अजमल कसाब ने प्रशिक्षण लिया था। इस जवाबी कार्रवाई के बाद भारत की कूटनीति अत्यंत सफल दिखाई दी थी क्योंकि अमेरिका, रूस और जापान ने भारत का तत्काल खुलकर समर्थन किया था। यह समर्थन मोदी ने वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए जो मुहिम चलाई हुई है, उसका परिणाम थी। इसमें दो राय नहीं कि सीमापार स्थित ठिकानों से आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले संगठनों के खिलाफ सेना और सुरक्षाबलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।

जलाशय से समृद्धि की राह: मोरगा की आदर्श मछुआ सहकारी समिति ने 25 परिवारों को दिया रोजगार और आत्मनिर्भरता का आधार

80 हजार के निवेश से 2.80 लाख का लाभ: मोरगा की मछुआ सहकारी समिति ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई इबारत

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जब प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग सामूहिक प्रयास तकनीकी मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सोच के साथ किया जाए, तो वही संसाधन ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और नियमित आय का मजबूत आधार बन सकते हैं मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम मोरगा की आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित ने अपनी मेहनत, सामूहिक प्रयास और विभागीय मार्गदर्शन से इसे साबित किया है वर्ष 2018 में गठित इस समिति में वर्तमान में 25 सदस्य हैं और समिति के अध्यक्ष आनंद सिंह हैं। मत्स्य विभाग के सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन से समिति ने जलाशय आधारित मत्स्य पालन को संगठित एवं वैज्ञानिक तरीके से अपनाया। आज मत्स्य पालन समिति के सदस्यों के लिए केवल मछली उत्पादन का कार्य नहीं, बल्कि रोजगार, अतिरिक्त आय और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है जलाशय के संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग, 25 सदस्यों को मिला रोजगार का आधार आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित मोरगा का पंजीयन 5 जून 2018 को हुआ था समिति का मुख्य उद्देश्य जलाशय में उपलब्ध मत्स्य संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए अपने सदस्यों को रोजगार एवं नियमित आय का साधन उपलब्ध कराना रहा है समिति द्वारा लगभग 11 हेक्टेयर जलक्षेत्र वाले जलाशय में सामूहिक रूप से मत्स्य पालन एवं मत्स्याखेट किया जाता है समिति के सदस्यों ने जल संसाधन को केवल पारंपरिक तरीके से उपयोग करने के बजाय इसे संगठित आर्थिक गतिविधि में बदलने का प्रयास किया मत्स्य विभाग के अधिकारियों से प्राप्त तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर जलाशय प्रबंधन, मत्स्य बीज संचयन, मछलियों की देखभाल, हार्वेस्टिंग और विपणन की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया। इससे सदस्यों को मत्स्य पालन के साथ उत्पादन, प्रबंधन और बाजार से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी भी प्राप्त हुई 80 हजार रुपये के निवेश से बढ़ी उत्पादन क्षमता, 3.50 लाख का वार्षिक कारोबार समिति ने पिछले वर्ष लगभग 80 हजार रुपये की लागत से मत्स्य बीज का संचयन किया विभागीय अधिकारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में जलाशय में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज डाले गए और जलाशय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। मछलियों के उचित आकार और वजन तक पहुंचने के बाद समिति के सदस्य सामूहिक रूप से उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके बाद मछलियों को स्थानीय बाजार तथा आसपास के क्षेत्रों में समिति के सदस्य स्वयं बेचते हैं। इससे समिति को उत्पादन के साथ सीधे विपणन का लाभ मिलता है। वर्तमान में समिति को जलाशय से लगभग 3.50 लाख रुपये का वार्षिक मत्स्य उत्पादन/कारोबार प्राप्त हो रहा है। पिछले वर्ष लगभग 80 हजार रुपये के निवेश के बाद समिति को लगभग 2.80 लाख रुपये का वार्षिक कुल लाभ प्राप्त हुआ। समिति के सदस्यों को लगभग 12 हजार रुपये प्रति सदस्य प्रतिवर्ष लाभांश वितरित किया जाता है मछली पालन के साथ खुद बिक्री भी बाजार से सीधे जुड़ रहे समिति के सदस्य समिति की सफलता का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सदस्य केवल मछली उत्पादन तक सीमित नहीं हैं हार्वेस्टिंग के बाद वे स्वयं स्थानीय बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में मछलियों का विक्रय करते हैं इससे सदस्यों को मछली की गुणवत्ता, हैंडलिंग, संरक्षण, बाजार की मांग और विपणन की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हो रही है मत्स्य विभाग द्वारा समय-समय पर सदस्यों को मत्स्य बीज संचयन, जलाशय प्रबंधन, मत्स्याखेट, मछलियों की हैंडलिंग, संरक्षण और विपणन से संबंधित तकनीकी जानकारी दी जाती है। इससे समिति के कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बेहतर प्रबंधन विकसित हुआ है कृषि के साथ मत्स्य पालन बना अतिरिक्त आय का मजबूत जरिया मत्स्य गतिविधियों से जुड़ने के बाद समिति के सदस्यों के लिए रोजगार और आय का एक नया स्रोत विकसित हुआ है पहले सदस्यों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और स्थानीय स्तर के अन्य कार्यों पर निर्भर थी। मत्स्य पालन को अतिरिक्त गतिविधि के रूप में अपनाने से उन्हें जलाशय से अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी समिति के सदस्य मत्स्य पालन के साथ कृषि गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं इस प्रकार कृषि और मत्स्य पालन का संयोजन परिवारों की आय में विविधता लाने और आजीविका को मजबूत करने में मददगार साबित हो रहा है नई तकनीक और नवाचार ने बनाया मत्स्य पालन को अधिक व्यवस्थित समिति द्वारा नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज का संचयन किया जाता है विभागीय तकनीकी सलाह के अनुसार जलाशय प्रबंधन किया जाता है ।

पिछले साल से 16.68 इंच कम बारिश, तवा डैम 54' खाली मूंग की सिंचाई पर मंडरा रहा संकट

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में इस मानसून अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते 20 अगस्त तक जिले में करीब 22.47 इंच बारिशदर्ज की गई है यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16.68 इंच कम है। कम बारिश का असर जिले के प्रमुख तवा डैम के जलस्तर पर भी दिखाई दे रहा है डैम फिलहाल करीब 46 फीसदी भरा है और 54 फीसदी खाली है सिंचाई विभाग के ईई अंकित सराफ के अनुसार तवा डैम का वर्तमान जलस्तर 1144 फीट है बैतूल और पचमढ़ी क्षेत्र से धीरे-धीरे पानी की आवक हो रही है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए डैम के 70 से 75 फीसदी तक भरने का अनुमान है यदि डैम पूरी क्षमता तक नहीं भर पाया तो अगले साल गर्मी में मूंग फसल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में परेशानी हो सकती है इसका सीधा असर नर्मदापुरम और हरदा जिले के किसानों पर पड़ सकता है पचमढ़ी में सबसे ज्यादा, माखननगर में सबसे कम बारिश जिले में अब तक सबसे अधिक 844 मिमी बारिश पचमढ़ी में दर्ज हुई है जबकि माखननगर में 352 मिमी बारिश हुई है। इसके अलावा सिवनी मालवा में 539 मिमी, इटारसी में 572 मिमी, सोहागपुर में 549 मिमी, पिपरिया में 553.6 मिमी, बनखेड़ी में 564.8 मिमी और डोलरिया में 481.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है मौसम विभाग ने जिले में 21 और 22 अगस्त को बारिश होने की संभावना जताई है हालांकि गुरुवार सुबह मौसम साफ रहा और धूप खिली रही किसानों और सिंचाई विभाग की नजर अब आगामी बारिश पर टिकी ह प्रमुख जलस्तर: सेठानी घाट 938.9 फीट, तवा डैम 1144 फीट, बरगी डैम 1382.8 फीट और बारना डैम 1138 फीट।

नर्मदापुरम में 5 कॉलोनियों में एक घंटे बिजली कटौती नए सब-स्टेशन से 20 से ज्यादा कॉलोनियों को मिलेगी राहत

मीडिया ऑडीटर,नर्मदापुरम (निप्र)। शहर में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मालाखेड़ी क्षेत्र में बनाए जा रहे नए 33/11 केवी सब-स्टेशन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। सब-स्टेशन शुरू होने के बाद मालाखेड़ी, चक्कर रोड, नर्मदा टाउन और आसपास की 20 से अधिक कॉलोनियों में बार-बार होने वाली बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है नए सब-स्टेशन से लाइन जोड़ने का कार्य गुरुवार को भी जारी रहेगा। इसके चलते नर्मदा टाउन फीडर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगा। बिजली कंपनी के अनुसार इस दौरान गोकुलधाम, सांईछत्र, रिशिपूरम, क्रिश्न रेसीडेंसी, वैदिक विहार, आईबीडी नेचुरल परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी अधिक लोड के कारण आती थी समस्या मालाखेड़ी रोड, नर्मदा टाउन, हाउसिंग बोर्ड और चक्कर रोड क्षेत्र में लंबे समय से बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की शिकायतें सामने आती रही हैं। मौजूदा फीडरों पर अधिक लोड होने के कारण गर्मी और बारिश के मौसम में समस्या बढ़ जाती थी। वहीं लाइन में खराबी या रखरखाव के दौरान कई क्षेत्रों में घंटों बिजली बंद रहने की स्थिति बनती थी इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए बिजली कंपनी ने मालाखेड़ी में नया 33/11 केवी सब-स्टेशन तैयार कराया है। इससे बिजली आपूर्ति का लोड विभाजित होगा और संबंधित क्षेत्रों में सप्लाई व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है जल्द शुरू होगी सप्लाई बिजली कंपनी के जोन-2 के एई राहुल कुमार ने बताया कि सब-स्टेशन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है नई लाइन जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है लाइन का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है जल्द ही टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर सब-स्टेशन से बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी नए सब-स्टेशन के चालू होने के बाद मालाखेड़ी और आसपास की 20 से अधिक कॉलोनियों के उपभोक्ताओं को बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

इटारसी में कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान बैठक: बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर, 80 लोगों ने ली सदस्यता

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। इटारसी स्थित जिला कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई बैठक में मध्यप्रदेश कांग्रेस की प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव उषा नायडू ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण से शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई इसके बाद प्रदेश प्रभारी उषा नायडू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पाण्डेय और नगर अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों और जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता को लेकर चर्चा की गई संगठन की मजबूती को बताया पार्टी की ताकत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उषा नायडू ने कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा आम लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की बात कही उन्होंने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए आंदोलनों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पाण्डेय ने प्रदेश प्रभारी के समक्ष जिले में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर किए गए आंदोलनों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की उन्होंने संगठन की मौजूदा गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी 80 नए कार्यकर्ताओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता बैठक के दौरान सोहागपुर और नर्मदापुरम क्षेत्र से आए करीब 80 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की जिला अध्यक्ष गुड्डन पाण्डेय ने नए सदस्यों का कांग्रेस का गमछा पहनाकर स्वागत किया इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और पार्टी की गतिविधियों को गांव एवं बूथ स्तर तक पहुंचाने का संकल्प लिया बैठक में कांग्रेस के जिला एवं स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक मौजूद रहे।

एमसीबी जिले में अब तक 819.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज, कोटाडोल में सबसे अधिक बारिश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। 1 जून से 20 अगस्त 2026 तक मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में कुल 819.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है जिला प्रशासन के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले की विभिन्न तहसीलों में वर्षा की स्थिति में अंतर देखने को मिला है जारी आंकड़ों के मुताबिक कोटाडोल तहसील में सबसे अधिक 952.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है वहीं खड़गवां तहसील में सबसे कम 615.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ तहसील में 923.2 मिलीमीटर, चिरमिरी में 852.1 मिलीमीटर तथा केल्हारी तहसील में 647.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है इसी क्रम में भरतपुर तहसील में अब तक 924.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है तहसीलवार आंकड़ों से स्पष्ट है कि कोटाडोल और भरतपुर क्षेत्र में इस मानसून अपेक्षाकृत अधिक बारिश हुई है जबकि खड़गवां और केल्हारी में वर्षा का आंकड़ा अन्य तहसीलों की तुलना में कम रहा है बारिश के चलते जिले के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है लगातार हो रही वर्षा से नदी-नालों में पानी का प्रवाह भी बढ़ा है प्रशासन द्वारा मौसम एवं वर्षा की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है जिला प्रशासन के अनुसार आगामी दिनों में मौसम की स्थिति को देखते हुए तहसील स्तर पर वर्षा संबंधी आंकड़ों का संकलन और निगरानी जारी रहेगी बारिश के आंकड़ों के आधार पर किसानों और आम नागरिकों को मौसम की परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है तहसीलवार वर्षा मनेन्द्रगढ़ 923.2 मिमी, चिरमिरी 852.1 मिमी, केल्हारी 647.0 मिमी, भरतपुर 924.5 मिमी, कोटाडोल 952.9 मिमी और खड़गवां 615.9 मिमी।

डिजिटल दुनिया में बेटियों की सुरक्षा पर जोर: नौगई स्कूल में साइबर सुरक्षा

जागरूकता कार्यक्रम संपन्न, छात्राओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के बताए महत्वपूर्ण उपाय

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगई में बालिकाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में छात्राओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच ऑनलाइन सुरक्षा, निजी जानकारी की गोपनीयता, मजबूत पासवर्ड, संदिग्ध लिंक और साइबर अपराधों से बचाव के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी गई कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को डिजिटल दुनिया का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग करने के लिए जागरूक एवं सक्षम बनाना रहा कार्यक्रम कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला सशक्तिकरण केंद्र हब की जिला मिशन समन्वयक श्रीमती तारा कुशवाहा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी व्यवहारिक जानकारियां सरल भाषा में समझाई गईं ताकि वे इंटरनेट का उपयोग करते समय संभावित जोखिमों को पहचान सकें और किसी भी साइबर धोखाधड़ी अथवा ऑनलाइन उत्पीड़न की स्थिति में सतर्कता बरत सकें निजी जानकारी साझा करने से बचने की दी सीख कार्यक्रम में बालिकाओं को विशेष रूप से समझाया गया कि इंटरनेट की दुनिया में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है उन्हें बताया गया कि अपना पूरा नाम, घर का पता, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी अथवा अन्य निजी विवरण किसी अनजान व्यक्ति के साथ ऑनलाइन साझा नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से आने वाले फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैसेज अथवा चैट का जवाब देने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई बालिकाओं को बताया गया कि साइबर अपराधी कई बार परिचित व्यक्ति बनकर या आकर्षक ऑफर, इनाम, नौकरी अथवा अन्य प्रलोभन देकर व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे किसी भी संदेश या अनुरोध पर तुरंत विश्वास करने के बजाय पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है मजबूत पासवर्ड और संदिग्ध लिंक से सावधानी कार्यक्रम में छात्राओं को मजबूत पासवर्ड बनाने के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसका अनुमान आसानी से न लगाया जा सके।

शराब के नशे में बेटे ने पिता से की मारपीट: लाठियों से हमला, घायल पिता जिला अस्पताल में भर्ती

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के ऊंची खरई गांव में गुरुवार रात पारिवारिक विवाद के दौरान एक युवक ने अपने 55 वर्षीय पिता के साथ मारपीट कर दी आरोप है कि युवक शराब के नशे में था और उसने लाठियों से पिता पर हमला किया घटना में घायल पिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है पीड़ित ब्रजमोहन जाटव (55), पिता प्रभु जाटव ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा विक्की (28) शराब का आदी है उनके अनुसार बेटे के कुछ दोस्त उसे यह कहकर भड़काते हैं कि पिता उसके साथ भेदभाव करते हैं और परिवार के अन्य बेटों का पक्ष लेते हैं ब्रजमोहन के मुताबिक गुरुवार रात विक्की शराब के नशे में घर पहुंचा। इसी दौरान उसने पिता से विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर विक्की ने लाठियों से उनके साथ मारपीट कर दी। हमले में ब्रजमोहन घायल हो गए। परिजन और आसपास के लोगों की मदद से उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है घायल पिता ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में कच्ची शराब की कथित बिक्री को लेकर भी चिंता जताई उनका आरोप है कि डाबरपुरा की कंजर बस्ती में कुछ लोग कच्ची शराब तैयार करते हैं उनका कहना है कि आसानी से शराब उपलब्ध होने के कारण गांव के कई युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं ब्रजमोहन ने प्रशासन और पुलिस से अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके।

हसदेव में दिखा बाढ़ का मॉक रेस्क्यू: एसडीआरएफ ने टापू, पुल और तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाने का किया जीवंत प्रदर्शन

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को परखने के उद्देश्य से तहसील नागपुर अंतर्गत हसदेव नदी इंटेकवेल एवं ग्राम पंचायत लाई स्थित वन विभाग नर्सरी परिसर में बाढ़ आपदा मॉकड्रिल का सफल आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभ्यास में बाढ़ की काल्पनिक स्थिति निर्मित कर राहत एवं बचाव कार्यों की पूरी प्रक्रिया को मौके पर जीवंत रूप से प्रदर्शित किया गया मॉकड्रिल में एसडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से नदी के टापू में फंसे ग्रामीणों, तेज बहाव में डूबते व्यक्तियों, पेड़ों की डालियों और पुल पर फंसे लोगों को मोटर बोट, रेस्क्यू रस्सियों एवं अन्य आधुनिक उपकरणों की सहायता से सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ढहे मकान में दबे लोगों के रेस्क्यू और सर्पदंश पीड़ित को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए 18 अगस्त 2026 को Table Top E&ercise (TTEX) आयोजित की गई थी इसके बाद मैदानी मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से प्रशासन एवं विभिन्न विभागों की वास्तविक समय में प्रतिक्रिया क्षमता, उपलब्ध संसाधनों, आपसी समन्वय, राहत-बचाव व्यवस्था और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण किया गया अभ्यास में बाढ़ की सूचना मिलने से लेकर सूचना तंत्र सक्रिय करने, इंसिडेंट कमांडर द्वारा निर्णय लेने, बचाव दलों की तैनाती और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को परखा गया। एसडीएम लिंगराज सिदार को इंसिडेंट कमांडर, डिप्टी कलेक्टर विजयेंद्र सारथी एवं शशि शेखर मिश्रा को सहायक इंसिडेंट कमांडर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था मॉकड्रिल की शुरुआत हसदेव नदी के टापू में बाढ़ के पानी के बीच फंसे ग्रामीणों के रेस्क्यू से हुई। प्रशिक्षित बचाव दल मोटर बोट एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ फंसे लोगों तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला इसके बाद तेज बहाव में डूबते व्यक्तियों को बचाने का अभ्यास किया गया। रेस्क्यू टीम ने लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, रेस्क्यू रस्सियों और मोटर बोट की मदद से प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने की तकनीक प्रदर्शित की। पेड़ों की डालियों और पुल पर फंसे लोगों को निकालने की कार्रवाई का भी जीवंत प्रदर्शन किया गया बाढ़ से ढहे मकान में दबे लोगों को निकालने तथा सर्पदंश पीड़ित को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराकर अस्पताल तक पहुंचाने की प्रक्रिया ने यह भी परखा कि एक साथ उत्पन्न होने वाली विभिन्न आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव दल कितनी तेजी और समन्वय के साथ कार्रवाई कर सकते हैं एसडीआरएफ की टीमों ने मॉक ड्रिल के दौरान आधुनिक बचाव तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन किया मोटर बोट, स्कूबा डाइविंग उपकरण, अंडरवाटर कैमरा, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, पेलिकन लाइट, सर्च लाइट और फायर ब्रिगेड सहित विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया गया खोरों ने नदी के गहरे पानी में डूबे या लापता व्यक्तियों की तलाश और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीक दिखाई अंडरवॉटर कैमरे के माध्यम से पानी के भीतर खोज अभियान की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई।

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, उपलब्ध सेवाओं तथा शिकायत निवारण व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा 19 अगस्त 2026 को ईई संचार-संधारण संभाग मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में फोरम के अध्यक्ष डी.के. सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कार्यशाला में मनेन्द्रगढ़ संचार-संधारण संभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. खाखा सहित सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे समस्या का समय पर निराकरण नहीं होने पर फोरम में शिकायत फोरम के अध्यक्ष डी.के. सैनी ने उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि बिजली बिल में त्रुटि, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी, विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्या तथा अन्य विद्युत सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का विभागीय स्तर पर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर उपभोक्ता विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं उन्होंने बताया कि फोरम द्वारा शिकायतों की सुनवाई कर नियमानुसार उनका निराकरण किया जाता है।

सिवनी में मानसून सक्रिय, 623 मिमी वर्षा दर्ज

1 जून से अब तक 623 मिमी पानी गिरा; नदी-नाले उफान पर

मीडिया ऑडीटर, सिवनी (निप्र)। सिवनी जिले में लगभग दो सप्ताह के अंतराल के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बुधवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा, जिससे जिले में 1 जून से अब तक 623.0 मिमी औसत संचयी वर्षा दर्ज की गई है। प्रशासन ने नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सिवनी मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार रात से ही बारिश शुरू हो गई थी, जो गुरुवार को भी जारी रही। दिनभर रुक-रुककर रिमझिम बारिश होती रही और गुरुवार सुबह से भी आसमान में बादल छाए रहे। इस बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम में ठंडक घुल गई है।

लगातार बारिश के कारण दैनिक कामकाज के लिए घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर सड़कें गीली होने से पैदल चलने वालों को आवागमन में दिक्कत हुई। जिले की नदियों, नालों, तालाबों और अन्य जलस्त्रोतों के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है।

प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। निर्देश दिए गए हैं कि यदि नदी, नाले, पुल या पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा हो तो उसे पार करने का प्रयास न करें। बारिश के दौरान बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचने की सलाह दी गई है। जिले में 1 जून से अब तक कुल 623.0 मिमी औसत संचयी वर्षा दर्ज की गई है। तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार, सिवनी में 711.0 मिमी, बरघाट में 698.2 मिमी, लखनादौन में 715.7 मिमी, केवलारी में 615.4 मिमी, कुरई में 513.6 मिमी, धनौरा में 612.0 मिमी, छपारा में 93.8 मिमी और घंसौर में 584.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हाल की अवधि में जिले में 1.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस बारिश से खरीफ फसलों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। धान, मक्का, सोयाबीन सहित अन्य फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिलने से किसानों को फायदा होगा। हालांकि, लगातार तेज बारिश होने पर खेतों में जलभराव की स्थिति बनने से फसलों पर प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है, इसलिए किसानों को जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है।

नर्मदापुरम में पिछले साल से 16.68 इंच कम बारिश हुई

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले में इस बार मानसून की शुरुआत से ही बारिश का दौर कमजोर बना हुआ है। रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण अब तक 22.47 इंच पानी बरसा है, जो पिछले साल की तुलना में 16.68 इंच कम है। कम बारिश का असर तवा डैम पर भी दिखाई दे रहा है, जो फिलहाल 46 फीसदी ही भरा है। बारिश के करीब 40 दिन शेष हैं, ऐसे में डैम पूरी तरह नहीं भरने पर अगले साल गर्मी की मूंग फसल की सिंचाई के लिए नर्मदापुरम और हरदा के किसानों के सामने जल संकट खड़ा हो सकता है।

तवा डैम 1144 फीट पर, 54% खाली: सिंचाई विभाग के ईई अंकित सराफ के मुताबिक तवा डैम का जलस्तर 1144 फीट है और डैम 54 फीसदी खाली है। बैतूल और पचमढ़ी क्षेत्र से धीरे-धीरे पानी की आवक हो रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए डैम के 70 से 75 फीसदी तक भरने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि डैम 100 फीसदी नहीं भरा तो मूंग फसल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है।

पचमढ़ी में सबसे ज्यादा, माखननगर में सबसे कम बारिश: जिले में ढाई माह में सबसे ज्यादा 844 मिमी बारिश पचमढ़ी में और सबसे कम 352 मिमी माखननगर में दर्ज हुई है। सिवनी मालवा में 539, इटारसी में 572, सोहागपुर में 549, पिपरिया में 553.6, बनखेड़ी में 564.8 और डोलरिया में 481.3 मिमी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 21 और 22 अगस्त को बारिश की संभावना जताई है। हालांकि गुरुवार सुबह से मौसम साफ है और धूप खिली हुई है।

नर्मदा और प्रमुख बांधों का जलस्तर: सेठानी घाट: 938.9 फीट तवा बांध: 1144.0 फीट बरगी बांध: 1382.8 फीट बारना बांध: 1138.0 फीट ।

इटारसी को मिली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस

भोपाल मंडल ने शुरू की नियमित सेवाएं ; मुंबई–प्रयागराज के बीच यात्रा होगी आसान

मीडिया ऑडीटर, इटारसी (निप्र)। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल को दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। प्रयागराज-लोकमान्य तिलक (टर्मिनस) और सुबेदारगंज-लोकमान्य तिलक (टर्मिनस) के बीच चलने वाली इन ट्रेनों का महत्वपूर्ण ठहराव इटारसी स्टेशन पर रहेगा। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मुंबई जाने वाले यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

प्रयागराज-लोकमान्य तिलक अमृत भारत (20436/20435): रवानगीः गाड़ी संख्या 20436 प्रयागराज जंक्शन से 21 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार शाम 6:10 बजे रवाना होगी। इटारसी समयः रात 3:35 बजे इटारसी पहुंचेगी और 3:45 बजे आगे बढ़ेगी। अगले दिन दोपहर 3:45 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। वापसीः गाड़ी संख्या 20435 लोकमान्य तिलक से प्रत्येक शनिवार शाम 5:20 बजे चलकर रात 2:50 बजे इटारसी और अगले दिन दोपहर 12:40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

सुबेदारगंज-लोकमान्य तिलक अमृत भारत (14121/14122): रवानगीः गाड़ी संख्या 14121 सुबेदारगंज से 27 अगस्त से प्रत्येक गुरुवार दोपहर 12:10 बजे रवाना होगी। इटारसी समयः अगले दिन सुबह 7:45 बजे इटारसी पहुंचेगी और रात 8:50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। वापसीः गाड़ी संख्या 14122 लोकमान्य तिलक से प्रत्येक शुक्रवार रात 10:55 बजे चलकर सुबह 11:05 बजे इटारसी पहुंचेगी।

इन प्रमुख शहरों के यात्रियों को मिलेगा लाभ: इन दोनों साप्ताहिक ट्रेनों के संचालन से इटारसी, सतना, जबलपुर, खंडवा, भुसावल, इगतपुरी और कल्याण जैसे प्रमुख स्टेशनों के यात्रियों को सीधी व आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी।

पिपरिया में दस दिन बाद बारिश, धान को फायदा

पिछले साल के मुकाबले 22 इंच कम बरसा पानी लोगों को उमस से मिली निजात

मीडिया ऑडीटर, पिपरिया (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया और आसपास के इलाकों में गुरुवार दोपहर 10 दिन के लंबे इंतजार के बाद तेज बारिश हुई। दोपहर करीब 2 बजे बादलों की गरज के साथ शुरू हुई आधे घंटे की तेज वर्षा और उसके बाद हुई बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। इस बारिश से सूख रही धान की फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद जगी है।

30 मिनट की बारिश से पानी-पानी हुई सड़कें: गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा था। दोपहर में आधे घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते नगर के मुख्य मार्गों और निचले इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। इस बारिश से लोगों को लंबे समय से सता रही गर्मी और उमस से काफी हद तक राहत मिली।

पिछले साल के मुकाबले 22 इंच कम बरसा पानी: मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्र में अब तक कुल 21.77 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि तक 43.58 इंच वर्षा हो चुकी थी। इस तरह इस सीजन में अब तक पिछले साल की तुलना में लगभग 22 इंच कम बारिश हुई है।

किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

इससे पहले क्षेत्र में 10 अगस्त को 73 मिमी बारिश हुई थी, जिसके बाद से केवल हल्की फुहारें ही पड़ी थीं। लंबे समय से बारिश न होने के कारण धान की फसल के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी, जिससे किसान चिंतित थे। गुरुवार को हुई इस बारिश ने धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है।

प्रतिबंध के बाद भी बन रहा था एनालॉग पनीर

सीहोर में डेयरी से 25 क्विंटल जब्त पैकेट पर कंपनी नाम-लेबलिंग भी गलत मिली

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए रुद्रांश डेयरी से 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया है। यह कार्रवाई पचामा गांव स्थित डेयरी पर की गई, जहां एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार प्रतिबंधित पनीर पकड़ा गया है। प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है।

संभागीय उड़नदस्ता भोपाल और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सीहोर की संयुक्त टीम ने रुद्रांश फैक्ट्री पर छापा मारा। उड़नदस्ता प्रभारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य आयुक्त को सीहोर में नकली और एनालॉग पनीर बनाए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

पैकेट पर लेबलिंग भी गलत थी: जांच के दौरान फैक्ट्री में नमक और शक्कर मिली। संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी ने बताया कि पनीर निर्माण में कई खामियां पाई गई। पैकेट पर कंपनी और उत्पाद का नाम नहीं था, साथ ही लेबलिंग भी गलत थी। जब्त किए गए 25 क्विंटल पनीर को सील कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, पचामा गांव स्थित रुद्रांश फैक्ट्री में लंबे समय से अमानक पनीर तैयार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में 12 अगस्त को एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी यहां इसका उत्पादन जारी था। इससे पहले भी, सूचना मिलने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सीहोर की टीम ने इसी फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 क्विंटल से अधिक एनालॉग पनीर जब्त किया था। उस कार्रवाई के बावजूद फैक्ट्री में एनालॉग पनीर का निर्माण नहीं रुका और लगातार बड़ी मात्रा में अमानक पनीर बनाया जा रहा था।

रीडिंग वैन में बच्चों को सुनाई गई प्रेरक कहानियां

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में संचालित रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आज चलित रीडिंग वैन कोठरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची। इस दौरान पठन एवं कहानी वाचन गतिविधियों का आयोजन किया गया। डाइट से सहायक प्राध्यापक डॉ अनीता बडगुर्जर भालेराव ने कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों को रोचक एवं प्रेरणादायक कहानियां सुनाई तथा उनसे संवाद कर पठन के प्रति रुचि विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को कहानी सुनाने के दौरान केवल तथ्यात्मक प्रश्नों तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें अपने विचार व्यक्त करने, कल्पना शक्ति विकसित करने और स्वयं की कहानियां गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, रचनात्मक सोच एवं आत्मविश्वास का विकास होगा। इस दौरान प्राचार्य एल्डमन तिर्की, मिशन अंकुर के श्री एस स्वर्णकार उपस्थित थे।

आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रसूता गुलाब बाई के हृदय रोग का इलाज व ऑपरेशन निशुल्क हुआ

मीडिया ऑडीटर, खण्डवा (निप्र)। विकासखण्ड खण्डवा के ग्राम खुटफल निवासी गर्भवती महिला श्रीमति गुलाब बाई पति पप्पू ने गत 2 जून को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जावर में एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया । इसके कुछ दिन बाद गाँव की आशा कार्यकर्ता मीरा पवार व आशा सुपरवाइजर शबनम ने गुलाब बाई के घर जाकर काउंसलिंग की तो उसने बताया कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। गुलाब बाई को फिर से जिला चिकित्सालय खण्डवा मे भर्ती करवाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा उसकी सोनोग्राफी, ईसीजी जांच कराई गई तो पता चला कि गुलाब बाई को हार्ट की समस्या है। अतः उसे हाईरिस्क श्रेणी में लेकर बेहतर प्रबंधन कर ईलाज किया गया है।

रायसेन में 8 दिन से बारिश नहीं:पिछले साल से 19.51 इंच कम पानी, बांध-तालाब आधे-अधूरे गेट खोलने की नौबत नहीं

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में पिछले आठ दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे नदी-नाले फिर से खाली हो गए हैं। इस साल 19 अगस्त तक जिले में औसत 654.63 मिलीमीटर (25.77 इंच) बारिश दर्ज की गई है। यह पिछले साल की इसी अवधि में हुई 1150 मिलीमीटर (45.28 इंच) बारिश से 495 मिलीमीटर (19.51 इंच) कम है। अगस्त माह में अब तक औसत बारिश की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत ही वर्षा हुई है। कम बारिश के कारण जिले के बांध और तालाब अपनी पूरी क्षमता से नहीं भर पाए हैं। इस सीजन में जलाशयों के गेट एक बार भी नहीं खोले गए हैं।

पिछले दिनों हुई तेज बारिश से नदी-नालों में पानी आया था, लेकिन बारिश का दौर थमने के बाद जलस्तर फिर से नीचे जाने लगा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए रायसेन में भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। जिले में वर्षाकाल की सामान्य औसत बारिश 1197.1 मिलीमीटर (47.13 इंच) मानी जाती है। ऐसे में किसानों और जलस्त्रोतों को अब एक और अच्छी बारिश का इंतजार है।

जानिए जिले में कहां कितनी बारिश हो चुकी: रायसेन में 579.8 मिमी (22.83 इंच), गैरतगंज में 775.8 मिमी (30.54 इंच), बेगमगंज में 782.1 मिमी (30.79 इंच), सिलवानी में 505 मिमी (19.88 इंच), गौहरगंज में 595.7 मिमी (23.45 इंच), बरेली में 492.2 मिमी (19.38 इंच), उदयपुरा में 844 मिमी (33.23 इंच), बाड़ी में 627 मिमी (24.69 इंच), सुल्तानपुर में 686.8 मिमी (27.04 इंच) और देवरी में 657.9 मिमी (25.90 इंच) बारिश दर्ज की गई है।

व्हाट्स ऐप चैटबॉट के माध्यम से अब किसान कर सकेंगे उर्वरक बुकिंग

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर किसानों की सुविधा के लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा उर्वरक बुकिंग के लिए व्हाट्स ऐप चैटबॉट सुविधा प्रारंभ की गई है। इस सुविधा के माध्यम से किसान सरल एवं सुविधाजनक तरीके से अपने मोबाइल से उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। किसान आधिकारिक WhatsApp Business (WABA) नंबर पर 'Help' या 'Fertilizer' लिखकर सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। उर्वरक बुकिंग की सरल प्रक्रिया 1. किसान WhatsApp पर 'Help' या 'Fertilizer' लिखकर चैट शुरू करेगा। 2. किसान अपना पंजीकृत आधार नंबर दर्ज करेगा। 3. आधार का सत्यापन होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। 4. OTP दर्ज करने पर किसान का प्रोफाइल विवरण प्रदर्शित होगा। 5. किसान अपनी भूमि का विवरण देखकर संबंधित जिले का चयन करेगा। 6. पात्र भूमि/खसरा के विरुद्ध फसल का चयन कर विवरण सुरक्षित करेगा। 7. किसान उर्वरक का प्रकार, उर्वरक एवं आवश्यक मात्रा का चयन करेगा। 8. किसान ब्लॉक, रिटेलर, कंपनी एवं पात्र उठाव तिथि का चयन करेगा। 9. सिस्टम उपलब्धता का सत्यापन कर त्तक्रकोड युक्त उर्वरक टोकन जारी करेगा। 10. किसान को WhatsApp पर टोकन, रिटेलर, उर्वरक, उठाव तिथि एवं टोकन की वैधता की जानकारी प्राप्त होगी। यह सुविधा उर्वरक बुकिंग प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं किसान-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण, शिविरों में हुआ शत-प्रतिशत समाधान

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। आम नागरिकों की बिजली प्रदाय संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन में मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याएं एवं शिकायतें प्राप्त कर उनका त्वरित निराकरण किया गया। विभाग द्वारा शिविरों में प्राप्त समस्याओं के शत-प्रतिशत समाधान की पहल की गई है। शिविरों में नवीन विद्युत कनेक्शन, नीचे लटक रहे विद्युत केबल एवं तारों को व्यवस्थित करने, मीटर संबंधी शिकायतों, स्मार्ट मीटर लगवाने, बिजली बिल एवं विद्युत भार बढ़ाने सहित अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। विद्युत विभाग की टीम द्वारा अधिकांश शिकायतों का मौके पर अथवा उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर त्वरित निराकरण किया गया। शिविर के दौरान श्री प्रयाग सिंह कुशवाहा ने घर में लगे विद्युत मीटर के तेज चलने तथा अधिक बिजली बिल आने की शिकायत दर्ज कराई। विद्युत विभाग की टीम ने शिकायत का मौके पर ही समाधान किया। इसी प्रकार कृष्णा कॉलोनी निवासी श्री सतीश चंद्र सक्सेना ने बिजली बिल का विद्युत भार बढ़ाने के लिए आवेदन दिया, जिसका विभागीय टीम द्वारा निराकरण कर दिया गया। श्री इरफान कुरैशी ने विद्युत मीटर लटकने की शिकायत की थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम उनके घर पहुंची और मीटर को व्यवस्थित कर दिया। कृष्णा कॉलोनी निवासी श्री जीएन शर्मा ने स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए आवेदन किया था। विद्युत विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके घर पहुंचकर स्मार्ट मीटर स्थापित किया। इसी तरह श्री कुलदीप मालवीय ने मीटर के नीचे लटक रही विद्युत केबल को व्यवस्थित करने के लिए आवेदन दिया। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर विद्युत लाइन को ऊपर कर व्यवस्थित किया। वहीं श्री रघुवर प्रसाद पासी ने नवीन विद्युत मीटर लगवाने के लिए आवेदन किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनके घर पहुंचकर नया मीटर स्थापित किया गया। विद्युत वितरण कंपनी की इस पहल से उपभोक्ताओं को अपनी बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। विभाग द्वारा शिविरों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

एग्रीस्टैक अभियान के तहत पात्र कृषकों की शत-प्रतिशत फार्मर आईडी बनाने पर जोर 20 अगस्त से 15 सितम्बर तक चलेगा प्रदेशव्यापी अभियान

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। रबी वर्ष 2026-27 में किसानों को उर्वरकों की आवश्यकता के अनुरूप समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, ई-विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरक टोकन सहित पोर्टल की विभिन्न सुविधाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने तथा अधिकाधिक किसानों को पैक्स की सदस्यता दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में 'एग्रीस्टैक पंजीयन, पैक्स सदस्यता एवं अग्रिम उर्वरक उठाव अभियान' आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान 20 अगस्त से 15 सितम्बर 2026 तक चलेगा। अभियान के दौरान पात्र कृषकों की फार्मर आईडी बनाने, लंबित बकेटिंग प्रकरणों का निराकरण करने, पैक्स में अधिकाधिक किसानों को सदस्य बनाने तथा केसीसी सेचुरेशन के लक्ष्य को पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर होगा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन: अभियान के तहत राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की जाएगी। ऐसे भूमिस्वामी जिनके खातों में हिस्सा निर्धारित नहीं है, उनके प्रकरणों में पटवारी स्तर पर परिमार्जन की गतिविधि प्रारंभ कर तहसीलदार स्तर से अनुमोदन कराया जाएगा, ताकि संबंधित किसान अपनी भूमि को फार्मर आईडी से जोड़ सकें। सारा पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड एवं रिपोर्ट के माध्यम से लंबित भूमिस्वामियों की सूची प्राप्त कर ऐसे किसानों की ग्रामवार सूची तैयार की जाएगी, जिनकी फार्मर आईडी अभी नहीं बनी है। यह सूची ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अभियान के दौरान छूटे हुए किसानों की पहचान कर उनका पंजीयन मिशन मोड में पूरा कराया जा सके। जिन किसानों की फार्मर आईडी पहले से बन चुकी है, लेकिन उनके सभी सर्वे नंबर आईडी से लिंक नहीं हैं, उनके शेष सर्वे नंबर स्न्डुह्द्दह्द ष्ठ्द्दह्लडुद्ब्यह्य श्चस्न्डुह्लद्द विकल्प के माध्यम से जोड़े जाएंगे। साथ ही, यदि किसी किसान की फार्मर आईडी में गलती से किसी अन्य किसान की भूमि जुड़ गई है, तो संबंधित रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन कर उसे दुरुस्त किया जाएगा।

किसानों को फार्मर आईडी के महत्व की दी जाएगी जानकारी: अभियान के दौरान किसानों को फार्मर आईडी की उपयोगिता के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। किसानों को बताया जाएगा कि फार्मर आईडी विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को गेहूं, चना, सरसों, धान, मूंग आदि फसलों के उपार्जन, उर्वरक प्राप्ति, अनुदान पर बीज प्राप्त करने, फसल प्रदर्शन, कृषि यंत्रों पर अनुदान तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने और ई-मंडी के माध्यम से कृषि उपज विक्रय के लिए भी फार्मर आईडी महत्वपूर्ण है।

विदिशा जिले में अब तक 47.81 प्रतिशत कार्य पूर्ण: 18 अगस्त 2026 की स्थिति में विदिशा जिले में 47.81 प्रतिशत पात्र कृषकों की फार्मर आईडी बनाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अभियान के तहत शेष पात्र कृषकों का पंजीयन प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। जिले में तहसीलवार एवं ग्रामवार प्रगति की लगातार समीक्षा करते हुए जिन कृषकों अथवा भूमिस्वामियों की फार्मर आईडी लंबित है, उनका चिन्हांकन कर मिशन मोड में पंजीयन कराया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अभियान के दौरान प्रत्येक तहसील में पात्र कृषकों की शत-प्रतिशत फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। फार्मर आईडी बनने से किसानों को कृषि संबंधी योजनाओं, उपार्जन, उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र एवं फसल बीमा सहित विभिन्न शासकीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्रशासन द्वारा किसानों से अभियान में सक्रिय रूप से सहभागिता कर अपनी फार्मर आईडी बनवाने तथा यदि आवश्यक हो तो अपनी भूमि एवं सर्वे नंबर से संबंधित जानकारी का सत्यापन कराने की अपील की गई है।

इंटर मियामी और फिलाडेल्फिया यूनियन मैच 2-2 से ड्रॉ

चेस्टर ,एजेसीं। मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) रेगुलर सीजन एक्शन में इंटर मियामी सीएफ और फिलाडेल्फिया यूनियन के बीच सुबारू पार्क में खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। मियामी के लिए कप्तान लियोनेल मेसी और डेनियल पिंटर ने 1-1 गोल किए। मेजबान फिलाडेल्फिया ने मैच का पहला गोल दागा। इंडियाना वासिलिव ने 11वें मिनट में शानदार गोल करते हुए टीम को बढ़त दिलाई। मियामी ने 21वें मिनट में गोल करते हुए बराबरी की। मियामी के लिए 21वें मिनट में डेनियल पिंटर ने गोल दागा। यह एमएलएस में पिंटर का पहला गोल था। पिंटर ने फुटबॉल इतिहास के दो बेहतरीन फुटबॉलर्स की मदद से अपने एमएलएस करियर का पहला गोल दागा। ये दो फुटबॉलर मेसी और लुईस सुआरेज थे। मेसी ने बॉक्स के बाईं ओर सुआरेज को गेंद दी, जिन्होंने हेडर से पास को मोड़कर पिंटर को बीच में पहुंचाया, जहां उन्होंने पास से बॉल को गोल पोस्ट में डाल दिया। इसके बाद मेसी ने 26वें मिनट में इस रेगुलर सीजन में अपना 13वां गोल करते हुए मियामी की बढ़त बनवाई। अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी को बॉक्स के दाहिने छोर पर फ्रे से गेंद मिली, फिर उन्होंने कट मारकर बॉल को दूर के पोस्ट पर कर्ल किया। इस बीच, यह असिस्ट इस रेगुलर सीजन में फ्रे का तीसरा असिस्ट था। हाफटाइम तक स्कोर 1-2 रहा। ऐसा लग रहा था कि मियामी इस मैच को जीत लेगी, लेकिन फिलाडेल्फिया ने 58वें मिनट में नील पियरे के गोल से मैच 2-2 से बराबर हो गया। इसके बाद दोनों ही टीमें गोल करने में असफल रही और मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इंटर मियामी अब रविवार को नु स्टेडियम में टोरंटो एफसी की मेजबानी करेगा। इंटर मियामी ने इस एमएलएस रेगुलर सीजन में अब तक 11 जीत, तीन हार और छह ड्रॉ दर्ज किए हैं। टीम के कुल 39 पॉइंट्स मिले हैं। मियामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर है।

काबुरा गेंद से अभ्यास मेरी सफलता का राज: मानव सुथार

गाले ,एजेसीं। श्रीलंका के खिलाफ गाले में खेले गए पहले टेस्ट में 10 विकेट लेकर भारत की 165 रन से जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार ने कहा है कि घर पर कूकाबुरा गेंद से किया गया अभ्यास उनके बहुत काम आया। बीसीसीआई द्वारा साझा एक वीडियो में सुथार ने कहा, 'अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के मैच के बाद कूकाबुरा गेंद के साथ तालमेल बिठाने पर ध्यान दिया था। घर और नेट्स दोनों पर इसी गेंद के साथ अभ्यास में काफी समय बिताया था। इसका फायदा पहले टेस्ट में हुआ। हम दस दिन पहले श्रीलंका आए थे। इससे माहौल के साथ तालमेल बिठाने और कूकाबुरा गेंद से खेलने में बहुत मदद मिली। मुझे तालमेल बिठाने का समय मिला।' सुथार ने कहा, 'मैं क्रिकेट को बहुत गंभीरता से लेता हूं। जब मैं अभ्यास करने जाता हूं तो मेरा ध्यान हर दिन बेहतर होने पर होता है। मैं जितना हो सके उतना अभ्यास करता हूं। अफगानिस्तान मैच के बाद मेरा ध्यान जल्द से जल्द तालमेल बिठाने पर था। मैंने कूकाबुरा गेंद के साथ बहुत अभ्यास किया। यह बहुत जरूरी था।' रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव से हुई बातचीत पर सुथार ने कहा, 'हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हम कितने सब्र से खेल सकते हैं। हम जानते थे कि नए बल्लेबाज के लिए इस विकेट पर खेलना मुश्किल होगा।' अपने प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर सुथार ने कहा, 'सबसे जरूरी बात यह है कि हमने मैच जीता। मैं इससे बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं कि टीम की जीत में अच्छा प्रदर्शन कर पाया। जीतना सबसे अच्छी बात है।' सुथार ने कहा, 'जीत के साथ सीरीज शुरू करना एक टीम के तौर पर हमारे लिए सकारात्मक है। इससे बहुत मदद मिलती है। जीतना सबको अच्छा लगता है।'

गुयाना अमेजन वारियर्स ने सेंट लूसिया किंग्स को 7 विकेट से हराया

सेंट लूसिया ,एजेसीं। कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2026 में डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए मुकाबले में सेंट लूसिया किंग्स ने गुयाना अमेजन वारियर्स को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट लूसिया किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए थे। चरिथ असलांका ने 28 गेंदों पर 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 35 रन बनाए। इसके अलावा एंड्रिज गॉस ने 20, कामिल पूरन ने 19, डैरोन नेड ने 17, मैथ्यू फोर्ड और कप्तान रोस्टन चेज ने 14-14 रन बनाए। गुयाना अमेजन वारियर्स के लिए ड्वायन प्रिटोरियस ने 3, शमार जोसेफ ने 2 और रोमारियो शेफर्ड ने 1 विकेट लिए। 152 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी गुयाना को ग्लेन फिलिप्स और मावेंद्र दिनदयाल ने तेज शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 10.3 ओवर में 79 रन जोड़े।

श्रीलंका पर जीत के बाद भारतीय कप्तान गिल ने पड्डिकल और सुथार की तारीफ की

गाले,एजेसीं। भारतीय क्रिकेट टीम ने गाले में खेले गए टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। शुभमन गिल के लिए एक बल्लेबाज के तौर पर यह मैच अच्छा नहीं रहा। वह दोनों पारियों में फ्लॉप रहे, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उनके लिए मैच संतोषजनक रहा। मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा, 'अपने देश के लिए 600वां टेस्ट मैच जीतना सच में बहुत खास है। हमारे लिए यह बहुत अच्छी जीत थी। मुझे लगता है कि हम एक आरामदायक स्थिति में थे। मौसम की वजह से पक्का नहीं था कि मैच होगा, या नहीं, हम पर थोड़ा दबाव था। लेकिन मुझे लगता है कि टीम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया।' दूसरी पारी में टीम की खराब बल्लेबाजी पर गिल ने कहा, 'चिंता की कोई बात नहीं है। हम तीसरी पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो लगभग 400 रन बनाना चाहते थे। विकेट पर अपनी मर्जी से रन बनाना आसान नहीं था। हम तीसरी पारी में थोड़ा आक्रामक होकर खेलना चाहते थे। हमें श्रीलंका को चौथी पारी में बल्लेबाजी देने के लिए पर्याप्त ओवर चाहिए थे, जबकि बारिश की वजह से कुछ भी निश्चित नहीं था। इसी वजह से शुरुआत में कुछ विकेट जल्दी गिरे, लेकिन मुझे लगता है कि हम आरामदायक स्थिति में थे।' मानव सुथार पर गिल ने कहा, 'वह शानदार गेंदबाजी कर रहा है। भारत में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले मैच में भी और इस मैच में भी उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वह बहुत होनहार खिलाड़ी लगता है और ऐसा कोई जो इंडिया के लिए बहुत लंबे समय तक खेल सकता है। देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी की और जरूरी शतक लगाया।

जोश टंग का अनोखा 'अर्धशतक', मिचेल स्टार्क को पछाड़ा

नई दिल्ली ,एजेसीं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच बुधवार से हेंडिग्ले में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हुआ। इंग्लैंड ने पहले दिन ही पाकिस्तान की पहली पारी 171 पर समेट दी। इंग्लैंड की तरफ से तेज गेंदबाजों ओली रॉबिनसन और जोश टंग ने 5-5 विकेट लिए। जोश टंग ने 5 विकेट लेने के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम हासिल की। टंग ने पाकिस्तान की पारी के दौरान 9.1 ओवर में 46 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। इस दौरान टंग मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) में 50 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। टंग ने 10 टेस्ट मैचों में 50 विकेट हासिल किए हैं। वह इस समय टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके पीछे ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क (48 विकेट) और भारत के मोहम्मद सिराज (41 विकेट) हैं। टंग मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक पारी में पांच विकेट लेने की उपलब्धि 3 बार हासिल कर चुके हैं। एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 50 या उससे अधिक विकेट लेने वाले टंग इंग्लैंड के छठे गेंदबाज बन गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक चक्र में सर्वाधिक विकेट लेने का इंग्लैंड का रिकॉर्ड पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम है। उन्होंने 2019-21 चक्र में 17 मैच खेलकर 69 विकेट लिए थे। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में कई मैच बाकी हैं, ऐसे में टंग ब्रॉड के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक चक्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन के नाम है। लियोन ने 2021-23 में ऑस्ट्रेलिया के लिए 20 मैच में 88 विकेट लिए थे। 28 साल के टंग ने 13 टेस्ट मैचों की 25 पारियों 62 विकेट लिए हैं। इस दौरान 4 बार एक पारी में 5 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के संन्यास के बाद टंग को टेस्ट क्रिकेट में बतौर तेज गेंदबाज इंग्लैंड का अहम हथियार माना जाता है।

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: त्रिशा-गायत्री का शानदार प्रदर्शन जारी

भारतीय जोड़ी ने कटाया क्वार्टर फाइनल का टिकट

नई दिल्ली ,एजेसीं। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने गुरुवार को बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए महिला डबल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी रिन इवानागा और की नाकानिशी को 21-16, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दुनिया में 39वें नंबर की भारतीय जोड़ी ने एक बार फिर अपनी रैंकिंग और सीडिंग से कहीं बेहतर खेल दिखाया और टूर्नामेंट की ऊंची रैंकिंग वाली जोड़ी को सीधे गेम में हरा दिया। अब सेमीफाइनल में जगह बनाने पर त्रिशा और गायत्री का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल पक्का हो जाएगा। इस जीत में त्रिशा के आक्रामक खेल की अहम भूमिका रही। भारतीय खिलाड़ी ने बार-बार कोर्ट के पिछले हिस्से से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अटैक के मौके बनाए। इसके साथ ही नेट पर भी उन्होंने कई शानदार शॉट खेले और जापानी जोड़ी को वापसी करने का मौका नहीं दिया। त्रिशा के अटैक के दौरान गायत्री का खेल थोड़ा शांत रहा, लेकिन उन्होंने तालमेल को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। कोर्ट पर त्रिशा के मूवमेंट और रोटेशन ने बार-बार इवानागा और नाकानिशी को मुश्किल स्थिति में डाला। हालांकि, इस मुकाबले में कुछ तनावपूर्ण पल भी देखने को मिले। त्रिशा और गायत्री खेल के दौरान कुछ घटनाओं से साफतौर पर परेशान दिखीं, क्योंकि जापानी जोड़ी के व्यवहार को लेकर उनकी चिंताओं पर उन्हें मनचाहा जवाब नहीं मिला। इसके बाद, शटल के साथ अपने व्यवहार के लिए चेयर अंपायर से चेतावनी मिलने के बाद त्रिशा को येलो कार्ड दिखाया गया। इस घटना से कुछ समय के लिए बैडमिंटन मैच पर असर पड़ने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन त्रिशा ने अपनी निराशा को बेहतरीन खेल में तब्दील किया। उन्होंने हर आक्रामक रैली में जबरदस्त तेजी दिखाई और सफल स्मैश के बाद जोरदार जश्न मनाया। स्टेडियम का माहौल जापानी जोड़ी के लिए और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि भारतीय समर्थकों ने मुकाबले को पूरी तरह से घरेलू मैच जैसा बना दिया था। एक समय तो त्रिशा मैच रेफरी से बहस करती रहीं, जब तक कि कोच पुलेला गोपीचंद ने कोर्ट के बाहर से उन्हें अपने कोने में वापस आने के लिए नहीं कहा। त्रिशा और गायत्री के लिए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाना उनकी वापसी की राह में एक और अहम पड़ाव है। त्रिशा को लगी चोट के कारण यह जोड़ी लगभग तीन महीने तक खेल से दूर रही, जिससे उन्हें वापसी के बाद अपनी लय फिर से हासिल करने की चुनौती का सामना करना पड़ा।

मैक्स वेरस्टैपेन ने रेड बुल के साथ अनुबंध 2030 तक बढ़ाया

नई दिल्ली ,एजेसीं। फॉर्मूला 1 में अपने भविष्य को लेकर चल रहे शक को दूर करते हुए, चार बार के वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वेरस्टैपेन ने अपनी रेड बुल टीम के साथ अनुबंध बढ़ाने पर हस्ताक्षर किया है। वह 2030 के आखिर तक आरबी22 के लिए रेस करेंगे। डचमैन, मैक्स वेरस्टैपेन के मैकलारेन में जाने की चर्चा चल रही थी। रेड बुल ने मैक्स वेरस्टैपेन के साथ अनुबंध बढ़ाने की घोषणा की पुष्टि की। टीम ने इस बात पर जोर दिया कि वेरस्टैपेन के साथ उनकी पार्टनरशिप 'एफ1' इतिहास की सबसे सफल और अहम साझेदारियों में से एक रही है। वेरस्टैपेन के साथ करार का बढ़ाया जाना आपसी भरोसे और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, साथ ही भविष्य को एक साथ आकार देने का एक साझा फैसला है। मैक्स वेरस्टैपेन, रेड बुल के साथ अपना अनुबंध बढ़ाकर खुश हैं। वह 2016 से बुल के साथ हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं अनुबंध बढ़ने से सच में बहुत खुश हूं। हमारे पास सबसे अच्छे लोग हैं। मैं फिर से शीर्ष पर वापस आने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करते रहने के लिए उत्साहित हूं। यह आखिरी लक्ष्य है जिसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं रेड बुल, लॉरेंट और ओरेकल रेड बुल रेसिंग में सभी को मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैक्स वेरस्टैपेन ने अपनी सारी सफलता रेड बुल सीरीज में ही पाई है। उन्होंने 2021 से मिल्टन कीन्स-बेस्ड टीम के साथ चार वर्ल्ड खिताब जीते हैं। उन्होंने 2024 तक लगातार चार खिताब जीते, जिसके बाद 2025 में लैंडो नॉरिस ने उनसे वर्ल्ड टाइटल छीन लिया।

डचमैन ने कहा, 'मैंने हमेशा कहा है कि टीम मेरे लिए दूसरे परिवार जैसी है। मुझे घर जैसा महसूस होता है। मैं टीम में रेस जीतने की उम्मीद से आया था। हमने साथ मिलकर जो हासिल किया वह बहुत प्यारा था। हमने कई शानदार पल साझा किए और चार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती।'

उन्होंने कहा, 'मैं जिस टीम के साथ मैं अपने पूरे करियर में रहा हूं, उसी के साथ इस सफर को जारी रखना वाकई खास है। लॉरेंट मेकीज को जुलाई 2025 में टीम प्रिंसिपल के रोल में प्रमोशन दिया गया। लॉरेंट के साथ अब एक साल से ज्यादा समय से काम करना भी बहुत अच्छा रहा है। मुझे टीम के लिए उनका एक साफ विजन दिखता है।

मिल्टन कीन्स में हर कोई उस चीज पर विश्वास करता है जो हम बना रहे हैं, और मैं अगले अध्याय का इंतजार कर रहा हूं। हम इस टीम का भविष्य बनाना जारी रखेंगे।' वेरस्टैपेन का एक्सटेंशन टीम के साथ मेकीज के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। उन्होंने कहा, 'मैक्स का हमारे साथ बने रहना और ग्रिड पर सबसे अच्छे ड्राइवर को बनाए रखना रेड बुल, ओरेकल रेड बुल रेसिंग, साथ ही 'एफ1' और पूरे मोटरस्पोर्ट में सभी के लिए शानदार खबर है।'

एसीबी ने नूर अहमद का एनओसी रद्द किया

सीपीएल से बाहर हुए अफगान स्पिनर

नई दिल्ली ,एजेसीं। कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2026 में सेंट लूसिया किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद सीपीएल के बचे मैचों में सेंट लूसिया किंग्स के लिए नहीं खेल पाएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने नूर अहमद उनका नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) रद्द कर दिया है। सेंट लूसिया किंग्स ने नूर अहमद के विकल्प के रूप में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर टिम सीफर्ट को साइन किया है। सेंट लूसिया किंग्स द्वारा जारी बयान में कहा गया, 'नूर अब बाकी टूर्नामेंट में सेंट लूसिया किंग्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। फ्रेंचाइजी इस बात से निराश है कि नूर टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।'

बयान में आगे कहा गया, 'सेंट लूसिया किंग्स टिम सीफर्ट का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, जो अभी स्क्वाड में शामिल होने के लिए सेंट लूसिया जा रहे हैं।' नूर ने 2020 में किंग्स (तब सेंट लूसिया जॉक्स) के साथ करार किया था। वीजा दिक्कतों की वजह से उन्हें उनके लिए खेलने का मौका नहीं मिला। सीपीएल 2024 में वह टीम के लिए खेले और 12 मैचों में 22 विकेट लेकर न सिर्फ टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज रहे, बल्कि टीम को चैंपियन बनाया। नूर का न होना निश्चित रूप से टीम के गेंदबाजी के लिए चिंता का विषय है। वहीं, टिम सीफर्ट को शामिल करना, किंग्स की बल्लेबाजी को मजबूती देगा। सीफर्ट बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही में 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए उनका प्रदर्शन शानदार रहा था और टीम की जीत में उनकी यादगार भूमिका रही थी। सिफर्ट 10 मैचों में 394 रन बनाकर टूर्नामेंट के दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे थे। फाइनल में सिफर्ट ने 38 गेंदों पर 72 रन की पारी खेल टीम को चैंपियन बनाया था और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। सिफर्ट पूर्व में सीपीएल में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (2020 से 2022) का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं।

अगले 12 महीने बेहद मुश्किल, 2023 वाली सफलता दोहराने का मौका: कैमरन ग्रीन

मैके ,एजेसीं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में पहला टेस्ट गंवाने के बाद अपने ऐतिहासिक 2023 कैंपेन से प्रेरणा ले सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट शनिवार से शुरू हो रहा है। बांग्लादेश सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसके बाद वनडे विश्व कप 2027 खेला जाना है। ग्रीन ने गुरुवार को मैके में कहा, 'ये 12 महीने सच में बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हमारे तीन सबसे मुश्किल विदेशी दौरे आने वाले हैं, दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड, साथ ही विश्व कप भी, इसलिए यह इस ग्रुप के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रोमांचक भी है। 2023 में हमारा शेड्यूल काफी मिलता-जुलता था और यह साल वाकई सफल रहा था, इसलिए हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं।'

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने माना कि लंबे विदेशी दौरे के दौरान निरंतरता बनाए रखना और मुश्किल हो जाता है।

उन्होंने कहा, 'विदेशी दौरे थका देने वाले हो सकते हैं, इसलिए बस एक-एक मैच के हिसाब से आगे बढ़ना है, बहुत आगे के बारे में नहीं सोचना है और बस इसका आनंद लेना है। ये बहुत लंबे दौरे हो सकते हैं, और उम्मीद है कि आप अपने परिवार को साथ ले जा सकते हैं और बस उस पल का आनंद ले सकते हैं।'

ग्रीन बैटिंग में ज्यादा सब्र रखने पर भी काम कर रहे हैं। उनका मकसद तेजी से रन बनाने के बजाय लंबी पारी खेलना है।

उन्होंने कहा, 'आप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते समय सच में अच्छा करना चाहते हैं। कभी-कभी आप उन नतीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से, टेस्ट क्रिकेट में आप 10

ओवर के अंदर शतक नहीं बना सकते, आपको वहां पहुंचने के लिए कुछ घंटे बैटिंग करनी पड़ती है। जब आपको लगता है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आप बहुत तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उस टेम्पो में आने की कोशिश करें जो काम करता है।'

ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया की 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश के खिलाफ डॉर्विन टेस्ट में शतक लगाकर उन्होंने फॉर्म में वापसी की है। हालांकि, शतक बनाने के बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया को हार से नहीं बचा पाए थे।

प्रकृति और अध्यात्म का अनूठा संगम मांदागिरी में मुचुकुंद ऋषि की तपोस्थली बनेगी छत्तीसगढ़ का नया पर्यटन केंद्र

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। धमतरी जिले के वनांचल नगरी (सिहावा) क्षेत्र की प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत में मेचका स्थित मांदागिरी पर्वत का विशेष महत्व है। नगरी विकासखंड के मेचका गांव के समीप मेखलाकार पहाड़ी पर स्थित मुचुकुंद ऋषि की तपोस्थली श्रद्धा, अध्यात्म और प्रकृति के अद्भुत संगम के रूप में जानी जाती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी (सिहावा) वनांचल में स्थित मांदागिरी पर्वत जल्द ही राज्य में धार्मिक, प्रकृति और साहसिक पर्यटन (ट्रेकिंग) के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। मेचका गांव के पास मेखलाकार पहाड़ी पर स्थित पौराणिक मुचुकुंद ऋषि की यह पावन तपोस्थली श्रद्धालुओं की आस्था के साथ-साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करने के लिए तैयार की जा रही है।

पौराणिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मुचुकुंद महाराज इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता के पुत्र थे। सुर-असुर संग्राम के बाद उनकी तपस्या से जुड़ा यह स्थल सिहावा-नगरी अंचल की 'सप्तऋषि तपोभूमि' की आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध करता है। मांदागिरी पर्वत पर सुंदर तालाब, प्राचीन प्रतिमाएं और माता सीता सहित देवी-देवताओं के मंदिर स्थित हैं। इसके अलावा, पहाड़ी की ऊंचाई से सोंढूर जलाशय (डेम) और विस्तृत वनांचल का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, जो ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन गंतव्य है। धमतरी के कलेक्टर ने बताया कि मांदागिरी की आध्यात्मिक और प्राकृतिक क्षमता को देखते हुए इसके समग्र विकास की योजना बनाई जा रही है। इस स्थल के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे पहुंच मार्ग, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। धार्मिक आस्था के संरक्षण के साथ-साथ ट्रेकिंग और एडवेंचर स्पॉट्स को चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ ही वनांचल क्षेत्र में पर्यटन से स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।नगरी से लगभग 27 किलोमीटर पूर्व स्थित यह स्थल आने वाले समय में राज्य के प्रमुख इको-टूरिज्म और पिलग्रिम टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से उभरेगा।

डॉ. पंकज शर्मा भारतीय मानक ब्यूरो की एग्रो-टेक्सटाइल्स समिति के अध्यक्ष नियुक्त

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर के संयुक्त निदेशक डॉ. पंकज शर्मा को उनके विशेषज्ञता, अनुभव और मानकीकरण गतिविधियों में निरंतर योगदान के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की एग्रो-टेक्सटाइल्स TXD 35 समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एग्रो-टेक्सटाइल्स समिति भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत गठित एक तकनीकी समिति है, जो एग्रो-टेक्सटाइल्स सामग्रियों एवं उत्पादों से संबंधित मानकीकरण कार्यों, जिसमें विनिर्देश, परीक्षण विधियां, तकनीकी शब्दावली तथा गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं, पर कार्य करती है। यह समिति एग्रो-टेक्सटाइल्स उत्पादों की गुणवत्ता, प्रदर्शन, सुरक्षा और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानकों के विकास एवं उनके पुनरीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रख्यात पादप रोग विज्ञानी डॉ. शर्मा को पादप रोग प्रबंधन, पादप-रोगजनक अंतःक्रिया तथा जैविक स्ट्रेस प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। इससे पूर्व वे भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, भरतपुर में प्रधान वैज्ञानिक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। डॉ. शर्मा ने फ्रांस स्थित रेपसीड एवं कैनोला नवाचार हेतु वैश्विक परिषद तथा वैज्ञानिक पैनल सहित कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक निकायों में योगदान दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी में आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मंचों पर भारतीय अनुसंधान का प्रतिनिधित्व किया है। डॉ. शर्मा वर्ष 2016 से एग्रो-टेक्सटाइल्स समिति के सक्रिय सदस्य रहे हैं। अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति भारतीय मानक ब्यूरो की मानकीकरण गतिविधियों में उनके दीर्घकालिक योगदान और वैज्ञानिक विशेषज्ञता की महत्वपूर्ण पहचान है। उनके नेतृत्व से समिति के कार्यों को गुणवत्ता मानकों, नवाचार, सतत विकास और वस्त्र क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति को और मजबूत करने में नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

पशुपालन बना आर्थिक समृद्धि का नया आधार KCC से 263 पशुपालकों को मिले 2.07 करोड़ रुपए

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। पशुपालन आज भारत और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा है, जो किसानों को नियमित आय, महिलाओं के लिए रोजगार और कृषि क्षेत्र के कुल मूल्य वर्धन में 30% से अधिक का योगदान देता है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पशुधन विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन की साझा पहल से पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा बनकर उभर रहा है। जिले में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ पशुपालकों को वित्तीय संबल देने के लिए चलाए जा रहे अभियानों के अब जमीनी और बेहद सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की आर्थिक मजबूती का आधार कलेक्टर के कुशल मार्गदर्शन और पशुधन विकास विभाग के उप संचालक के सतत प्रयासों से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड (AHD) योजना के जरिए आर्थिक मजबूती दी जा रही है। इस वर्ष मार्च 2026 से जून 2026 के बीच विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को कुल 408 प्रकरण भेजे गए थे, जिनमें से 263 हितग्राहियों को 2 करोड़ 07 लाख 25 हजार 375 रुपए का आसान और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदाय किया जा चुका है। वित्तीय सहायता मिलने से किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और वे तेजी से आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।

37 बकरी पालकों को 24 लाख 28 हजार 313 रुपए का लाभ पहुँचाया गया: इस पूरी सफलता की कहानी में वित्तीय संस्थानों की भूमिका भी बेहद सराहनीय रही है। जबकि इन्हीं क्षेत्रों के 37 बकरी पालकों को 24 लाख 28 हजार 313 रुपए का लाभ पहुँचाया। वहीं एचडीएफसी बैंक ने 88 प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 53 लाख 26 हज़ार 129 रुपए का ऋण वितरित किया। 33 हितग्राहियों को कुल 26 लाख 50 हजार 848 रुपए का चष्ष्ट ऋण उपलब्ध इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने मवेशियों के भरण-पोषण और गाय पालन के लिए बरमकेला और सारंगढ़ के 33 हितग्राहियों को कुल 26 लाख 50 हजार 848 रुपए का चष्ष्ट ऋण उपलब्ध कराया। साथ ही, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक हितग्राही को 2 लाख 285 रुपए और बैंक ऑफ इंडिया ने एक हितग्राही को 1 लाख 20 हजार रूपए की राशि स्वीकृत कर पशुपालन को बढ़ावा देने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया दृश्य संवाद 2026 का शुभारंभ

तस्वीरों में उतरा छत्तीसगढ़, फोटो जर्नलिस्टों का हुआ सम्मान रायपुर प्रेस क्लब में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट 'दृश्य संवाद 2026' का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में रायपुर के प्रेस फोटो जर्नलिस्टों के साथ-साथ प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में तस्वीरों के जरिए प्रकृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा तथा जनसरोकार से जुड़े विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।चार कैटेगरी में आयोजित प्रदर्शनी की 'प्रकृति एवं पर्यावरण' कैटेगरी में प्रदर्शित तस्वीरों ने प्रदर्शनी स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य को साकार कर दिया। वहीं 'संस्कृति एवं परंपरा' कैटेगरी की तस्वीरों में छत्तीसगढ़ की लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की महक महसूस की जा सकती है। 'समाचार एवं जनसरोकार' कैटेगरी में फोटो जर्नलिस्टों की नजर से महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक सरोकारों को एक क्लिक में जीवंत रूप दिया गया है। इस वर्ष रायपुर प्रेस क्लब ने प्रदर्शनी को और व्यापक स्वरूप देते हुए प्रेस क्लब के गैर सदस्य प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों के लिए भी ओपन कैटेगरी में भागीदारी का अवसर दिया। इस श्रेणी में 35 से अधिक प्रतिभागियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं।

फोटोग्राफी चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम : श्याम बिहारी जायसवाल प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फोटो जर्नलिस्टों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि फोटोग्राफी केवल कैमरे से तस्वीर खींचने का काम नहीं, बल्कि एक पल को इतिहास के लिए सुरक्षित कर देने की कला और जिम्मेदारी है। खासतौर पर फोटो जर्नलिज्म में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होतीं। फोटो जर्नलिस्ट को घटनास्थल पर मौजूद रहकर बेहद कम समय में यह तय करना होता है कि कौन-सा क्षण महत्वपूर्ण है और उसे किस एंगल से कैमरे में कैद किया जाए। उन्होंने कहा कि एक अच्छी तस्वीर के पीछे तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, सही समय की पहचान, सही एंगल और परिस्थितियों को समझने की दृष्टि भी जरूरी है। कई बार पत्रकार घटना को शब्दों में विस्तार से बताते हैं, लेकिन एक तस्वीर वही बात एक क्षण में लोगों तक पहुंचा देती है। यही फोटो जर्नलिज्म की ताकत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन सराहनीय पहल है। इससे वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्टों के अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचेंगे और युवा तथा शौकिया फोटोग्राफरों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। उन्होंने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं दीं।

कृषक उन्नति योजना से बदली किसान दिलीप की तकदीर आधुनिक कृषि यंत्रों से संवार रहे क्षेत्र की खेती

धान की बेहतर आय को खेती के आधुनिकीकरण में लगाया, 28 एकड़ में पैडी ट्रांसप्लांटर से कराई रोपाई

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना किसानों की आय को मजबूत करने के साथ उन्हें आधुनिक और लाभकारी खेती की दिशा में आगे बढ़ा रही है। योजना से प्राप्त बेहतर आय का उपयोग कर किसान न केवल अपनी खेती का स्वरूप बदल रहे हैं, बल्कि आसपास के किसानों को भी आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ उपलब्ध करा रहे हैं। बालोद जिले के ग्राम बोड़ेना निवासी प्रगतिशील किसान श्री दिलीप कुमार साहू इसकी प्रेरणादायी मिसाल हैं। धान से मिली आय का खेती के आधुनिकीकरण में निवेश श्री दिलीप कुमार साहू ने कृषक उन्नति योजना के तहत 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का विक्रय किया। धान से प्राप्त बेहतर आय का उपयोग उन्होंने पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने में किया। खेती की लागत कम करने, श्रम की आवश्यकता घटाने और समय पर रोपाई पूरी करने के उद्देश्य से उन्होंने पैडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई मशीन) खरीदी। उन्होंने अपने 28 एकड़ खेत में मशीन के माध्यम से धान की रोपाई कराई। मशीन से कम समय और सीमित मानव श्रम में बड़े रकबे में रोपाई पूरी होने से खेती की लागत में कमी आई। साथ ही मशीन द्वारा पौधों के बीच निर्धारित एवं समान दूरी बनाए रखने से फसल के बेहतर विकास और अधिक उत्पादन की संभावना भी बढ़ी है।

किसान से बढ़कर बने क्षेत्र के किसानों के सहयोगी: दिलीप कुमार की आधुनिक तकनीक से खेती का परिणाम देखकर आसपास के किसानों में भी पैडी ट्रांसप्लांटर के प्रति रुचि बढ़ी। किसानों की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने अब दो पैडी ट्रांसप्लांटर मशीनें उपलब्ध कर ली हैं। वे अपने गांव के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में किसानों के सैकड़ों एकड़ खेतों में समय पर धान रोपाई का कार्य कर रहे हैं। इससे क्षेत्र के किसानों को मजदूरों की कमी के बीच बड़ी राहत मिल रही है। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में ही उपलब्ध होने से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है।

आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा ग्रामीण क्षेत्र: किसान दिलीप कुमार साहू का अनुभव बताता है कि सरकारी योजनाओं से प्राप्त आर्थिक मजबूती का उपयोग यदि कृषि में तकनीकी निवेश के लिए किया जाए तो किसान स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरे किसानों के लिए भी अवसर तैयार कर सकता है। पैडी ट्रांसप्लांटर जैसी मशीनों के उपयोग से धान की खेती अधिक समयबद्ध, श्रम-कुशल और वैज्ञानिक हो रही है। 'कृषक उन्नति योजना ने किसानों को आधुनिक खेती का रास्ता दिखाया' किसान श्री दिलीप कुमार साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कृषक उन्नति योजना ने किसानों की मेहनत को बेहतर आर्थिक आधार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि योजना से मिली आय को खेती के आधुनिकीकरण में लगाकर उन्होंने न केवल अपनी खेती को आसान बनाया, बल्कि अब क्षेत्र के अन्य किसानों को भी आधुनिक कृषि यंत्रों की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाली इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

स्वामित्व से सशक्तिकरण: धमतरी ने रचा नया कीर्तिमान 50 हजार से अधिक परिवारों को मिला ज़मीन का 'कानूनी हक'

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में एक मौन क्रांति आकार ले रही है। दशकों से अपनी ही ज़मीन और आशियाने पर बिना किसी ठोस कानूनी दस्तावेज़ के रह रहे हज़ारों परिवारों के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'स्वामित्व योजना' एक नया सवेरा लेकर आई है। इस योजना के सटीक, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के मामले में धमतरी जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर एक शानदार मिसाल कायम की है। धमतरी के गांवों में आज उत्साह का माहौल है। जब जिले के 50 हजार से अधिक पात्र परिवारों के हाथों में उनकी आबादी भूमि का अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) पहुँचा, तो वर्षों से अपने ही घर के मालिकाना हक को लेकर मन में बनी असमंजस की स्थिति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। आधुनिक तकनीक और धरातली सत्यापन का अनूठा संगम धमतरी जिले की इस बड़ी सफलता के पीछे आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक मुस्तैदी का बेजोड़ समन्वय रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया' (SOI) के तकनीकी सहयोग से जिले के 501 राजस्व ग्रामों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य सफलता पूर्वक पूरा कराया गया। ड्रोन सर्वे से प्राप्त नक्शों को केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि राजस्व टीमों ने गाँव-गाँव जाकर स्थल सत्यापन किया। आबादी भूमि के अभिलेखों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया ताकि बनने वाला हर 'अधिकार पत्र' पूरी तरह शुद्ध और प्रामाणिक हो।इस कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि अब तक 312 गांवों के अभिलेख पूरी तरह डिजिटल बनाकर पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अधिकार पत्र से खुलेंगे आर्थिक समृद्धि के नए द्वार केवल एक दस्तावेज़ मिल जाने से ग्रामीणों की ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, अब ग्रामीण अपनी आबादी भूमि के कानूनी दस्तावेज़ों के आधार पर बैंकों से आसानी से होम लोन, व्यवसाय ऋण या अन्य वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे।

सिंधी सेवा महिला विंग ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू से की सौजन्य

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू से छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महिला विंग के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. ममता साहू को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुलाकात के दौरान महिला विंग की प्रतिनिधियों ने महिलाओं से जुड़े विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में राज्य महिला आयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। इस अवसर पर श्रीमती भावना कुकरेजा, श्रीमती साधना गुरनानी, श्रीमती कुसुम डोडवानी, श्रीमती कुसुम, श्रीमती अनीता, श्रीमती हेमा, श्रीमती पाखी, श्रीमती मंजू एवं श्रीमती ज्योति सहित सिंधी समाज की महिलाएं उपस्थित रहीं।

जरहाभाठा छात्रावास परिसर : पीपीपी मॉडल पर मल्टी स्टोरी भवन के रूप में होगा विकसित

रायपुर। आदिम जाति और कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज बिलासपुर में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ उनके लाभ को अधिक से अधिक किसानों, ग्रामीणों और हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री नेताम ने कृषि एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं और उनके माध्यम से किसानों को मिलने वाले लाभ की जानकारी केवल कागजों तक सीमित न रहे। योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के साथ उन्हें योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ और परिणाम भी दिखाया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इनसे जुड़कर अपनी आय और उत्पादन में वृद्धि कर सकें। उन्होंने उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए किसानों को अधिकाधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फलदार एवं उपयोगी पौधों के रोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए विभागीय योजनाओं के माध्यम से किसानों को पौधे उपलब्ध कराने तथा रोपण के बाद उनकी देखभाल के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने पर भी जोर दिया। बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत छात्रावासों में प्रवेश की स्थिति की भी जानकारी ली गई। मंत्री श्री नेताम ने छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाओं तथा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने जरहाभाठा स्थित विभागीय छात्रावास परिसर को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूप में विकसित करने की जानकारी दी। यह भवन पीपीपी मॉडल के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों के लिए बेहतर एवं आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मंत्री श्री नेताम ने मत्स्य विभाग सहित सभी विभागों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से मैदानी स्तर पर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा किसानों एवं हितग्राहियों से सतत संवाद बनाए रखने को कहा।

कुंदनपाल में शुरू हुआ नया आधार सेवा केंद्र, अब गांव में ही मिलेंगी आधार संबंधी सुविधाए

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और सुशासन की सोच के अनुरूप शासन की जरूरी सेवाएं अब गांवों तक आसानी से पहुंच रही हैं। सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत कुंदनपाल में नए आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। केंद्र शुरू होने से अब ग्रामीणों को आधार संबंधी काम के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में कुंदनपाल में आधार सेवा केंद्र की शुरुआत ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगी। 'एक ही जगह मिलेगी आधार की कई सुविधाएं' नए आधार सेवा केंद्र में नया आधार कार्ड बनवाने के साथ नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा फिंगरप्रिंट और आईरिस जैसे बायोमेट्रिक अपडेट भी कराए जा सकेंगे। गांव में ही यह सुविधा मिलने से बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को विशेष राहत मिलेगी। इससे उनका समय और आने-जाने का खर्च भी बचेगा। 'सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में होगी आसानी' आधार कार्ड आज कई शासकीय योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का महत्वपूर्ण आधार है। राशन, आयुष्मान भारत, छात्रवृत्ति और विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की जानकारी सही और अद्यतन होना जरूरी है। आधार सेवा केंद्र शुरू होने से ग्रामीण अपने आधार में जरूरी सुधार समय पर करा सकेंगे और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में उन्हें सुविधा होगी।

'गांव तक पहुंच रहा डिजिटल सुशासन': कुंदनपाल में आधार सेवा केंद्र की शुरुआत यह दर्शाती है कि शासन की प्राथमिकता केवल शहरों तक सुविधाएं पहुंचाना नहीं, बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी जरूरी सेवाएं उनके गांव के पास उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सोच और वन एवं प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में ऐसी पहल ग्रामीणों के जीवन को सरल बनाने के साथ डिजिटल सेवाओं के प्रति विश्वास को भी मजबूत कर रही है।

डी.डी.ओ. के बैंक खातों में जमा अव्ययित राशि की जानकारी 7 दिनों में उपलब्ध कराने के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधीन विभिन्न विभागों के डी.डी.ओ. के बैंक खातों में 31 मार्च की स्थिति में पिछले पांच वर्षों में जमा अव्ययित राशि (Unspent Balances) की जानकारी संकलित कर ई-कोष पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इस संबंध में 14 अगस्त 2026 को आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न विभागों के 42 बजट नियंत्रक अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में हुई चर्चा के अनुसार सभी बजट नियंत्रक अधिकारियों को अपने अधीनस्थ समस्त डी.डी.ओ. के बैंक खातों में 31 मार्च की स्थिति में पिछले पांच वर्षों के दौरान जमा अव्ययित राशि की जानकारी निर्धारित प्रारूप में तैयार कर 07 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय के ई-मेल एवं बीसीओ व्हाट्सएप ग्रुप पर सॉफ्ट कॉपी के साथ भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यशाला में कार्यालय संचालक, कोष एवं लेखा के ई-कोष पोर्टल (Tag Integration) से संबंधित तकनीकी टीम के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान ई-कोष पोर्टल में पिछले पांच वर्षों में डी.डी.ओ. के बैंक खातों में स्थानांतरित राशि की जानकारी दर्ज करने तथा प्रारूप में स्थानांतरित बैंक खाता नंबर, पूर्वशेष सहित अन्य आवश्यक विवरणों में सुधार एवं बदलाव को लेकर तकनीकी चर्चा की गई। समस्त बजट नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने अधीनस्थ डी.डी.ओ. से पिछले पांच वर्षों की अव्ययित राशि की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रारूप में E&cel File के साथ निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराएं। साथ ही कार्यालय संचालक, कोष एवं लेखा के समन्वय से उक्त जानकारी को शीघ्र ई-कोष पोर्टल पर भी दर्ज कराया जाए।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी
आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा